साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 12 अंक 17 | प्रति सोमवार, इंदौर, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर 2017 | पृष्ठ 12 मूल्य 2/- रुपए

■ बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया, भर ले खूब थैला, साथ न जायेगा धैला ■

पूंजीपतियों के इशारे पर ढीठ मोदी ने तबाही मचाई देश में

अपनी सभी नीतियों की असफलता के गुणगान पर भी अरबों रुपए प्रसार माध्यमों पर जन धन की बर्बादी

पट्टे की आजाद भारत के इतिहास में नरेन्द्र मोदी जैसा घोर बकवादी, झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री दूसरा कोई नहीं हुआ और शायद न कोई होगा। उसकी चुनाव पूर्व भाषण शैली से यह तो स्पष्ट था ही कि ये घोर ढीठ जो चुनावी वादे कर रहा है। उन्हें पूरा करने की तो दूर सत्ता पाते ही गिरगिट के रंग बदलने की प्राकृतिक प्रक्रिया को शर्मिंदा करते हुए सत्ता को बाप की जागीर मान, सत्ता का भारी दुरुपयोग करेगा। आते ही जन-धन से विश्व भ्रमण पर जनहितों की आड़ में पूजीपति आकाओं के लिए राष्ट्र हितों को बलाये ताक पर रख उनके व्यावसायिक हितों को साधने में लगा रहा। जब देश की जनता और प्रसार माध्यमों ने ज्यादा हो हल्ला किया तो राष्ट्र की जनता के मस्तिष्क से अपने कुकर्मों की सफाई करने स्वच्छ भारते के नाम स्वयं अपने हाथों में झाड़ू थाम खड़ा हो गया

जैसे जनता ने इसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निर्धनता, आतंकवाद, महंगाई, सफाई करने की अपेक्षा, सफाईकर्मियों को निगमों, पालिकाओं की सफाई व्यवस्था को झुठलाते हुए इन्हें सड़कों पर झाड़ू उठाकर सफाई करने के लिए सत्ता सौंपी हो। बदलें में जनता पर सफाई उपकर सौंप देश की निगमों और पालिकाओं की सफाई के नाम उगाही की पूरी छूट दे दी। अब निगम, पालिकाओं, करों, सरकार उपकर से और निगम कर्मचारी सीधे ही जनता से लूटपाट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूंजीवादियों के रखैल मोदी ने पूंजीपतियों के लिए पहले नोटबंदी से देश में तबाही मचाई, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लघु उद्योगों व बड़े उद्योग नगदी की कमी से बंद हो गए, यह सब जानने के बाद भी ढीठ भाजपाई 1 वर्ष बाद भी नोटबंदी की तारीफ कर पोस्टर बैनरों से पूरे देश को पाट दिया। वही हाल जीएसटी का भी हुआ, ये भी पूंजीपतियों के लाभ के लिए, ज्यादा करों की झंझटों से बचाने और मोटा लाभ दिलाने के लिए इतने बिलष्ट तरीके से बनाया गया, ताकि आसानी से उस क्लिष्ट कानून की धाराओं उपबंधों का लाभ उठाकर देने से बचा जाये और छोटा व्यापारी, उद्योगपति उनमें उलझकर, कर चोरी के आरोप में सजा का पात्र बने और अपने उद्योग, व्यापार को बंद कर दे ताकि इन बड़े पूंजीपतियों की छोटे उद्योगों व्यापारियों, दुकानदारों से प्रतिस्पर्धा समाप्त हो और ये गिद्धों की फौज जनता की विदेशों की तरह भूखा मार लूटते रहे।

(शेष पेज 9 पर)

रेत माफिया शिवराज ने अपने व्यापार को सुगम बनाने बनाई नई रेत खनन नीति

नदी, तल और पर्यावरण करेंगे नई रेती उलीचने की नीति से धूर्त मुख्यमंत्री चौहान भ्रष्टाचार, छल-कपट के लिए कानून बनाने व बदलने के भी 12 वर्ष में मास्टर बने

मप्र के मुख्यमंत्री रहते हुए चौहान अपने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रेती, बस भूमाफियां, कॉलोनी माफियाओं, सरकारी निर्माण कार्यों, आपूर्ति आदि के व्यवसाय से मोटी कमाई और कमीशन के लिए खूब कानूनों में संशोधन किए और अनेकों नए कानून बनाने में भी 12 वर्ष में न्यायाधीशों और वकीलों से बड़े मास्टर बन गए। अपने भू हड़पू ने कॉलोनी काटने वाले कमल दल के सदस्यों की परेशानी और भूमाफियाओं से मोटे कमीशन के मिलते, भू कानून बदले, संशोधित और बनाए गए।

जिसमें किसी की भी जमीन, मकान, जायदाद को हड़पने बिना मुआवजे के व्यवस्था की गई, सामान्य वर्ग को उन्नति न देने अपने व्यापमं कांड से बचने सर्वोच्च न्यायालय में मोटा धन खर्च कर संविधान के समानता के अधिकार का मजाक उड़ाने दिशा बदली गई, पेशियों पर पेशियां लगवाई गई। जनधन कितना भी बर्बाद हो चलेगा, कर्ज ले लेकर घी पीने वाले और अपनी लूट-खंसोट को कानूनी जामा पहनाने अपने भ्रष्टाचार के रेत खनन के आरोपों से बचने, सच बोलने वालों को सत्ता की मदहोशी में जेल करवाने वाले ने अपने रेत के व्यापार को निर्बाध चलाने के लिए नई रेत नीति बनाकर, सरकार को अरबों रुपए प्रतिवर्ष की रायल्टी का घाटा पहुंचाने, गांव की पंचायतों के सरपंचों जो बेचारे पंचायत संभाल नहीं पाते, खनन माफिया से कैसे रायल्टी वसूलेंगे। फिर बेइंतहा नदियों से रेत खनन से नदी तक खोखले होने के साथ पर्यावरण भी बिगाड़ेंगे। पर इस हरामखोर को इससे क्या लेना-देना।

मध्यप्रदेश सरकार की नई रेत उत्खनन नीति पर प्रश्न उठाते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अचानक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि "नौ सौ चुहे खाने के बाद बिल्ली हज पर चली" जैसी कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है।

(शेष पेज 2 पर)

जन, जंगल, जमीन को नोंचा खाया प्रदेश कर दिया कंगाल

ऋण ले, घी पिया, किया भ्रष्टाचार का तांडव

विदेश यात्राओं, निवेश के लिए हरकदम, हर विभाग में भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, सड़के, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बदहाल

मप्र के मुख्यमंत्री बने शिवराज को 12 वर्ष होने पर अरबों रुपए के जनधन से करों में वसूले गए धन से विज्ञापन बांटे, सरकारी खर्च पर अपनी वाहवाही के लिए तालियां ठुकवाने लाखों लोगों को इकट्ठा कर रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा बर्बाद किए गए और नगदीहीन व्यावसायिक व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रशिक्षण देने का बहाना किया गया, इस पर भी तुर्रा यह कि सब बड़ी सादगी से किया गया। अपने बाप की जागीर नहीं जनता से डीजल, पेट्रोल और गैसों में वसूले जा रहे 32 प्रश वेट, जिसका 70 प्रश पैसा केवल अपनी वाहवाही के विज्ञापन छपवाने और समाचार चैनलों पर अपनी जालसाजी और भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यशैली अपने घोटालों, जनता के साथ लूट के कारनामों को प्रसारित न करने के लिए ही बांटे जाते है। बदले में मीडिया के भांड, जनता के भ्रामक विकास के सब्जबागों के शब्दों में उलझाकर, भ्रष्टाचारों, जालसाजियों, अपराधों के यथार्थ को छुपाते है। आखिर क्यों नहीं देता मप्र का जनसंपर्क विभाग अपने विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों से संबंधित और किसको कितना, जन-धन के माध्यम से विज्ञापनों में लुटाया सूचना के अधिकार में, मप्र के महालेखाकार द्वारा पकड़ी जानी, व अंकेक्षण की आपत्तियां सार्वजनिक क्यों नही की जाती।

बेमिसाल 12 वर्ष में मु.मं. शिवराज बताये कि किस विभाग में करोड़ों के घोटाले नहीं हुए, एक तरफ इन सबके दबाने छुपाने हजारों करोड़ के हर वर्ष विज्ञापन बांटे तो दूसरी तरफ सरकार चलाने के लिए धन की कमी का रोना रोकर बाजार से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज जनता के माथे पर ही सरकारी संपत्तियों को बतौर सुरक्षा प्राप्ति भूमि के रूप में रख लिया जाता है। बदले में सरकार चलाने के नाम सरकार ऋण हजारों करोड़ का, अपनी झूठी वाहवाही और तारीफों न केवल देश के वरन विदेशों में भी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, दृष्य माध्यमों से लेकर होर्डिंग्स, बेनर्स भी कभी सिंहस्थ के तो कभी 6 करोड़ वृक्षारोपण के युरोपीय देशों तक में करवाकर जनधन बर्बाद करने पर तुली रहती है।

(शेष पेज 9 पर)

■ बीजिंग और अन्य महानगरों की धुंध से सबक नहीं ले सके ■

दिल्ली की प्रदूषित धुंद से 10 करोड़ की जिंदगी खतरे में, जिम्मेदार कौन?

मानवीय लालच, जंगलों की कटाई, हरियाली की सफाई, नदियों, तालाबों पर कब्जे, बहाव क्षेत्र की भराई से कॉलोनियां, फैक्ट्रियां, पहाड़ों, जंगलों को मिट्टी-गिट्टी के लालच में अंधाधुंध खुदाई, चारों तरफ कांक्रीट के जंगल, कमीशन के लिए कार निर्माताओं की खूली लूट, कारों, दो पहिया वाहनों की बिक्री हर वर्ष 50 लाख से ज्यादा वाहन सड़कों पर, ये है तरक्की का पैमाना या धीमी मौत का दावतखाना

दिल्ली में 8-9 नवम्बर से ठंड की दस्तक के साथ धुंध, कोहरे ने भी अपनी आमद कर दी, यह धुंध साधारण धुंध नहीं थी, तापमान गिरने के साथ हवा में दिल्ली में दौड़ रहे 1 करोड़ से ज्यादा ट्रकों, कारों, दो पहिया वाहनों के धुंये से निकले कार्बन मोनोआक्साइड अन्य कार्बनिक यौगिकों के कणों के साथ धूल भी जमी हुई थी जो तापमान के कारण नमी के साथ दिल्ली की जलवायु में 5-10 फीट की ऊंचाई से लेकर 400-800 फीट तक जमे होने के कारण सूरज की रोशनी भी

धुंधलाने के कारण सैकड़ों वाहन अनेकों स्थानों पर टकरा गए थे। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, आगे चलकर ये सब परेशानियां श्वसन, त्वचा, ह्दय, दृष्टिगत, आंखों की साधारण से गंभीर बीमारियों में परिणत होगी ही। इसकी व्याख्या बड़े समाचार पत्रों और दूरदर्शनी समाचार श्रृंखलाओं ने लगातार पिछले सप्ताह से जारी है। यह धुंध न केवल दिल्ली वर दिल्ली से लगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से लेकर पड़ोसी पाकिस्तान के लाहोर तक सबको चपेट में ले रही है। आखिर विदेशी महानगरों और बीजिंग की पिछले वर्षों में छाई धुंध और उसकी परेशानियों से हमने शीघ्र सबक क्यों नहीं लिया, हम चोट, परेशानी व संकट में घिरे बिना हमारी नियती ही नहीं है कि इस संचार साधनों की आधुनिकता से कुछ सीख सके,

(शेष पेज 8 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

यहां ईमानदार वह जिसे मौका नहीं मिला

राष्ट्र प्रेम का अभाव, राष्ट्र का दुर्भाग्य

भारत की उर्वरा भूमि ही, भारत का दुर्भाग्य बन गई, यहां की निश्चित जलवायु, उर्वरा भूमि ने जहां देश की धरती पर जन्में लोगों को, राजाओं से लेकर वर्तमान सत्ताधीश नेताओं को घोर स्वार्थी, मक्कार, भ्रष्ट और जालसाज बना दिया। यही कारण था कि ये देवी-देवताओं की जन्म स्थली का, ऋषि-मुनियों के ज्ञान पुंज का देश जिसने पूरी दुनिया की ज्ञान गणित दिया वह देश हजारों साल से गुलामी का दंश झेल रहा है। इसका सबसे मूल कारण था कि इस देश की धरती ने यहां पर सभी सुविधाओं को देकर यहां के लोगों को घोर स्वार्थी, मक्कार, कामचोर, आलसी बना दिया, जिससे उनमें परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति जो घोर समर्पण भाव चाहिए था, विकसित ही नहीं हो पाया। यही कारण था कि चंद राष्ट्र भक्तों को बहुसंख्यक घोर स्वार्थी मक्कारों ने न सुना, न समझा, परिणाम में सहस्त्रों वर्षों से आक्रमणकारियों, हूणों, श्कों, मुगलों, डच, पुर्तगीज और अंग्रेजों ने एक तरफ देश की जनता पर अत्याचार किए तो दूसरी तरफ प्राकृतिक साधनों का भरपूर दोहन किया। वर्तमान में भी यही हो रहा है। चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की हो। सत्ता संभालते ही सब धन और रुपयों के लालच में देश की बर्बादी से नहीं चूक रहे हैं। भाजपा जो अपने आप को बड़ा राष्ट्रभक्त बताती थी पूंजीपतियों के लिए नोटबंदी, जीएसटी लाद दिया जिससे चारों तरफ घोर बर्बादी, बेरोजगारी बढ़ गई। अब करोड़ों लोगों की बेरोजगारी, उद्योग धंधे, व्यापार बर्बाद कर दिए। अपनी असफलताओं को छुपाने जनधन के अरबों रुपए के विज्ञापन बांट मीडिया का मुंह बंद किया जा रहा है। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज ने सत्ता संभालते ही हर कदम भ्रष्टाचार किया। नर्मदा खोखली कर रेत उलींची, 56 प्रजातियों के पेड़ों के काटने की छूट देकर पूरे वन उजाड़ दिए, सस्ती विद्युत बेंचनें में और महंगी खरीदने में मोटा कमीशन हजम किया तो दूसरी तरफ प्रदेश के उपभोक्ताओं को कीमतें बढ़ाकर लूटने, बिजली के तेज मीटर, अनाप-शनाप बिलिंग कं. के घाटों की पूर्ति करने के लिए थोपे जाकर राक्षसों की भांति तांडव मचा रहे हैं। मात्र धन हड़पने लूटने के लिए। न इस हरामखोर जालसाज को जनता की पीड़ा दिख रही है। आखिर कब तक कितना जनता को नोचोंगे। वोटों की खातिर, सत्ता हथियाने और सत्ता के माध्यम से मोटी कमाई करने के लिए ये सब किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे ये नेता अपने चंद स्वार्थों की खातिर इस देश औरे देश की जनता को नीलाम करने से नहीं चूकते हैं। चाहे वह मोदी हो, शिवराज, वसुंधरा या ममता बजर्नी। जिनकी चर्चा और भ्रष्टाचार के किस्से कहानियां दबे छिपे समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। फिर भी ये जनता को यथार्थ से दूर अपने शब्दों के मायाजाल में उलझा उन्हें भयभीत करने, डराने, चमकाने से लेकर अपनी मोटी कमाई के लिए कभी आधार कार्ड की तरह धकेलते हैं। तो कभी खाते खुलवाकर रुपए 15-15 लाख खातों में जमा करवाने का लालच दे। उल्टे ही भारी करों से, महंगाई से, देश में फुटकर व्यवसाय, रक्षा में, बैंकों और बीमा व्यवसाय आदि में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश मोटा कमीशन हड़प करें, न्यौता दे गुलाम बनाने में जुटे हैं। यह जानकार भी कि इससे देश की बर्बादी होगी, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा इन धूर्तों को इससे कोई मतलब नहीं इनके लिए तो बाप बड़ा न भय्या, सबसे बड़ा रुपैया। यह जानकर की कितना ही भर लो थैला, साथ न जायेगा थैला। फिर भी राष्ट्र प्रेम को त्याग, जनता को उल्टे ही राष्ट्र भक्ति का पाठ पढ़ा, स्वयं विदेशियों को न्यौता देश को गुलाम बनाने पर तुले हैं।

सर्वोच्च न्यायालय निजी गोपनीयता की मान्यता की वैधानिकता केवल सैद्धांतिक

आधार कार्ड प्राधिकरण, मोबाइल, इंटरनेट, ई-मेल, सोशल साइट्स सब लूट रहे डाटा से

आधारहीन करना ही उद्देश्य, आधार कार्ड बहुराष्ट्रीय कं. की कमाई के लिए ही नंदन नीलकेणी के साथ पी. चिदंबरम ने थोपा था, अमेरिकी गूगल से मिलकर चीन और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास भी है। भारतीय जनता का सारा डाटा, इसी के दम पर हैकर्स जनता के खातों से दुनिया में कहीं से भी पैसा गायन कर देते है। पर बहुराष्ट्रीय कं. और पूंजीपतियों के लिए आधार कार्ड बन बनवाना मोबाइल चलाने, गाड़ी और बैंक खाता रखने के निर्देशों के बाद भी अनिवार्य। एक आधार कार्ड नंबर से दुनिया में बैठकर कहीं से भी भारत के हर व्यक्ति की गाड़ी, बैंक खाते, मोबाइल नंबर घर का पता, मकान, दुकान, व्यवसाय, पत्नी, बच्चों के, माता-पिता के नाम और बर्बाद कीजिये जैसे करना हो, कैसा सर्वोच्च न्यायालय की गोपनीयता का पालन बैंकों के कर्मचारी डाटा बेंचकर पर से सरकारी शूकरों की फौज चुप है।

भारत की जनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य सिद्ध हुआ, पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. की गुलाम मुखेरा जन पार्टी के सबसे मूढ़, मवाली नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, जिसने 14-15 वर्ष से लेकर 30-35 वर्ष तक मवाली गिरी की हो, पढ़ा न लिखा, बाद मेंबचने के लिए रा. स्व.से.सं. में शामिल हो, 25-50 वाक्य राष्ट्रभक्ति के लिए और मंचों से मुंह चलाना सीख गया, इसके बीच सेवक बन संघ कार्यालयों में से सभी नेताओं को गोपनीय राज लेकर डरा धमकाकर विधायक का टिकट ले, मुख्यमंत्री और इसी तरह प्रधानमंत्री बन बैठा, पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. के धन को पहले सोशल मीडिया और प्रचार माध्यमों पर फूंक खूब झूठे वादे कर सत्ता हथिया ली। स्वाभाविक था पूंजीपतियों का ये गुलाम अब जनता को लुटवाने उसके आधार कार्ड के माध्यम से उसे कंगाल और भिखारी बनाने पर तुला है।

बैंकों से धन गायब करवाया जा रहा है हजारों का रोज आधार कार्ड और मोबाइल से खाता लिंक करवाने पर स्वयं बैंककर्मियों और मोबाइल कं. के कर्मचारियों द्वारा हर रोज डाटा बेंचकर, हर दिन ये बाते सामने आ रही है। आखिर जनता अपनी आकस्मिक और दीर्घगामी आवश्यकताओं यथा बीमारी,चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, शादी-ब्याह, मकान बनाने, बुढ़ापे के लिए बचत करने के उद्देश्य से ही पैसा बैंकों में जमा करवाता है, पर ऐसे 78 प्रतिशत गरीब व निम्न मध्यम वर्गीय को बिना बताये, बिना सूचित किए सभी सरकारी बैंकों विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक ने 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों का जनधन के नाम खुले खातों में न्यूनतम शेष के नाम हड़प कर, गरीबों को और गरीब बनाया दूसरी सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही गोपनीयता के अधिकार को ही आम आदमी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता आधार कार्ड से लिंक न करने की छूट दे दी हो, परंतु जनहितों से खिलवाड़ करने उनके डाटा को बेंचने, उन की हर बचत पर निगाह रखने, कालेधन की आड़ में लघु बचत करने वालों की एक तरफ तो ब्याज दरें कम कर दी दूसरी तरफ न्यूनतम शेष, 5 से ज्यादा लेन-देन करने पर सौदा शुल्क सेवा कर लगाकर बिना कुछ किऐ गरीब जनता के रुपए 4 लाख करोड़ से ज्यादा हड़प लिये। अकेले स्टेट बैंक ने जबकि यहां शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी न केवल घोर भ्रष्ट बत्तमीज है।

इन जालसाजों ने ग्राहकों के डाले हुए पीवाई मार्ग शाखा के चेक गायब गरीब जनता के रुपए लाख करोड़ से ज्यादा हड़प लिए। अकेले स्टेट बैंक में विलीन हुआ तब उन शूकरों के स्थानांतरण वर्षों बाद हुये। तो वर्तमान में तो बिना बैंक में घुसे ही किसी भी मोबाइल नंबर से आधार कार्ड, आधार कार्ड से बैंक खाते खोल और ईमेल हैक कर असानी से रोज ही खाते खाली हो रहे हैं और क्या कर लेती है, सरकार, पुलिस और हर बैंक में बैठी जालसाजों की ये फौज जो स्वयं ऐसे हैकरों को सूचना देकर ,ातों से रकम उड़वाने में सहयोग करती है। देशभर में बैंक जालसाजियों के मामलों में अनेक बैंककर्मियों की संदिग्ध भूमिका पाई गई। फिर पैसा निकलने के बाद बैंक, पुलिस शिकायत लेने में भी आनाकानी करती है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस आधार कार्ड का डाटा सरकार ने तैयार किया है। वो अमेरिका स्थित गूगल के कार्यालय में भी संग्रहित हुआ है। जब भारत सरकार के सूचना तकनीकी विभाग का अपना राष्ट्रीय स्तर पर दमदार क्षेत्र ही विकसित नहीं किया है। जिससे न केवल आधार कार्ड का, वरन सभी बैंकों का ऑनलाइन चलने वाली प्रणालियां अमेरिका स्थित माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय से चल रही है। जिसे कोई साधारण योग्यता का व्यक्ति आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर जान व देख सकता है और देख रहा है। जो कई रूस, चीन, पाकिस्तान से हैक की जा चुकी है। डाटा चुराया जा चुका है। जब सरकार का डाटा ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के आधार कार्ड, मोबाइल नं., बैंक खातों सुरक्षा की क्या बिसात, फिर हाल ही में इंदौर में पकड़े गए कांडों से मोबाइल कं. में बैठे कर्मचारी ही दूसरी कं. के कर्मचारियों का डाटा बेंचकर उनके ग्राहकों को फोनकर अपनी कं. में आने या नई सिम लेने की सलाह आखिर कहां से देते हैं दूसरे और बीएसएनएल बनाम भ्रष्ट, शूकर, निकम्मा, लूटेरों का यह सरकारी तंत्र को बर्बाद करने तो, स्वयं देश के प्रधानमंत्री, संचार मंत्री से लेकर नीचे तक जिसको जैसा मौका मिलता है, बर्बाद करने का प्रयास करता है, इसका डाटा भी देश की सैकड़ों कं. को बैंचा गया, यही कारण है कि उसके हर मोबाइलधारक के पास विभिन्न सारे दिन दोस्ती करो, तुम बहुत बहुत जाहिल और गंवार हो, आज रात मैं अकेली हूं, कब तक तरसाओगे मुझे आदि के मैसेज आते रहते हैं। अर्थात इस भ्रष्ट, शूकर, निकम्मा, अनलिमिटेड के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आखिर डाटा बेंचा है। इस गिरोह को यह सालों से चला रहा है। सरकार के शूकरों की फौज डाटा की गोपनीयता की तो दूर स्वयं ही डाटा बेंचकर मोबाइल धारकों की जानकारियों के माध्यम से नीलाम करने पर तुली है। जिससे सबसे ज्यादा खतरा शासकीय पदों पर बैठे अधिकारियों और निरीक्षकों के ही है। मोबाइल नंबर की जीपीआरएस प्रणाली से आतंकवादी, अपराधी उस अधिकारी निरीक्षक, न्यायाधीश की सही स्थिति जानकर अभी नहीं तो कभी भी घात करेंगे।

प्र.मं. मोदी, वित्त मंत्री जेटली व इनका सारा गिरोह घोर मक्कार, झूठा, फरेबी और भ्रष्ट है। जो पूंजीपतियों के लाभ के लिए पूरे सरकारी तंत्र को चौपट करने के साथ ही जनता को भी चौपट करने पर तुला है। जनता के आधार कार्ड से मोबाइल, गाड़ी, बैंक खाता, मकान, दुकान, पेन नंबर, टिन नंबर, सब जोड़ देने के बाद, हर गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है, उन्हें चोर कहता है। परंतु स्वयं हरामखोरों और जालसाजों का अड्डा, मंत्रियों, न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक करता है न कही आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ना चाहता है। ये हरामखोर गिद्धों की फौज जैसे अमर फल खाकर पैदा हुई है, जिसे जनता की तो सांस लेने और छोड़ने की भी जानकारी होनी चाहिए, परंतु अपन स्वयं सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर तीन माह तक पत्रों को ही इधर-उधर करते रह पर किसी ने एक लाइन की जानकारी नहीं दी।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जब गोपनीयता के प्रमुख माना और निजी भौतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है तो, बैंकों के माध्यम से जनता को आधार कार्ड नंबर देने, मोबाइल नंबर देकर सारी गोपनीयता भंग करने पर तुले है। स्वयं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को इसे न्यायालयीन अवमानना मानकर सरकार को सबको आधार कार्ड से जोड़ने आम जनता को नीलाम करने की नीति को तत्काल रोकना चाहिए।

रेत माफिया शिवराज ने अपने व्यापार को सुगम बनाने बनाई नई रेत खनन नीति

पेज 1 का शेष

विगत 12 वषी से बड़ी-बड़ी पोकलैण्ड मशीनों से समस्त नियमों कानूनों को धज्जियॉ बिखेरकर भाजपा मंत्रियों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों द्वारा अवैध उत्खनन कर दोनों हाथों से रेत को लूटने के बाद एक ऐसी नीति बनाई गई है जो निश्चत रूप से असफल सिद्ध होगी। इसके पीछे एक मात्र कारण है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के चेहरे पर अवैध उत्खनन की जो कालिख लगी है उसे साफ करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। शासन की यह रेत उत्खनन नीति भी भावांतर की तरह भयावह सिद्ध होगी। कांग्रेस नेताजी ने कहा कि इस नीति में उत्खनन का अधिकार प्रदान करने की शक्ति ग्राम पंचायतों को दी गई है जिनके पास ना तो आवश्यक अमला है और नाही रेत उत्खनन की मापदण्डों के अनुसार खनन की विशेषज्ञता, ऐसे में खनन माफिया एवं ठेकेदार जिन पर अभी तक खनिज एवं पर्यावरण विभाग का अंकुश था, अब वह निरकुंश होकर रेत का मनमाने ढंग से उत्खनन कर एक ओर जहॉ शासन को करोड़ों रूपये की रायल्टी का चुना लगाऐंगे वहीं नदियों के पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुॅचाऐंगे, क्योंकि जब प्रदेश का खनिज एवं पुलिस विभाग भी मिलकर अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगा सके थे तब एक अदना सरपंच किस प्रकार रेत माफिया से मुकाबला कर सकेगा, ऐसे में राज्य शासन की इस नई रेत उत्खनन नीति से जहॉ राजस्व का भारी नुकसान होगा वहीं रेत माफिया की आपसी प्रतिद्वन्दिता से प्रदेश की कानून व्यवस्था भी छिन्द भिन्न हो जावेगी। प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार भावांतर के भंवर में किसानों को उल्झा दिया है वहीं इस रेत उत्खनन की नई नीति से प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बिगड़ने की आशंका है। सरकार को इस नीति पर समग्र रूप से विचार करने के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिये। पर कांग्रेस नेता की इस बात की कोई महत्वायें धूर्त चौहान कोई महत्व नहीं देगा। सत्ता व जन धन उनके बाप की जागिर की तरह है, जिसे वो सत्ता में रहने तक लूटेंगे। विदेशों में होटल खड़ी करेंगे।

● भ्रष्टाचार जालसाजियों को मत देख- हेलमेट पहन घोड़े की तरह दौड़, सीधा देख ●

अपने भ्रष्टाचार छुपाने फिर क्षे.प.अ. का लाइसेंस निरस्ती का तांडव

इंदौर में मोटा चंदा बांटकर आने वाले हर अधिकारी का चाहे वह आयुक्त हो, जिलाधीश, निगमायुक्त, डायरायुक्त, श्रमायुक्त, आयकरायुक्त, अधिकारी उपायुक्त, उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सहा. आबकारी आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण, लोक स्वा. यांत्रिकीय, जलसंसाधन ग्रामीण यांत्रिकीय, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास सड़क, संयुक्त संचालक कृषि, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा आदि के राज्य व केन्द्र के शासकीय विभागों में बैठते ही दोनों हाथों से बटोरने और कमजोर कड़ी कौन को दबाकर समाचार पत्रों में कार्यवाही कर नायक बनने का नाकाम प्रयास करते हैं। बाद में मुंह की खाकर औंधे मुंह बिदाई लेते है। यह पिछले 15-17 वर्षों से प्रशासनिक स्तर पर नौटंकी की देखने को मिल रही है।

इंदौर संभाग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है इंदौर संभाग के 8 जिलों में तीनों प्रदेशों से निजी व सार्वजनिक सेवाओं के ट्रकों और बसों का निरंतर यातायात बना रहता है। स्वाभाविक है कि परिहवन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी की मोटी कमाई का साधन है। हजारों गलत नंबर के वाहन, वर्षों से बिना नंबर की दोपहिया, चार पहिया गाड़ियां निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की जिसमें अधिकांश नगर निगम की गाड़ियां, ट्रक, पानी के टैंकर, जिसमें नंबर प्लेट की तो दूर, पूरा ये लाल रंग के ट्रक टेंकर का सामने का कांच तक नहीं है। इंदौर की सड़कों पर यह खुला तांडव करते घूमते हैं। निगमायुक्त, पार्षदों, महापौर, पुलिस से लेकर संभागायुक्त, जिलाधीश, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को नहीं दिखते हैं। उन्हें अंतरप्रांतीय बसों और प्रांतीय बसों पर लंबे मार्गों पर चलती है। लदा हुआ टनों से इन सबकी सरपरस्ती में लदा हुआ माल नहीं दिखता है। ट्रकों से लेकर लोडिंग वाहनों में लदा हुआ बाहर तक निकला हुआ सरिया विद्युत कं. के लदे हुए खंभे जो 5-5 फूट तक निकले रहते है ट्रक की बॉडी से, जिससे अचानक गाड़ी रोकने पर पूरे देशभर में हर वर्ष हजारों लोगों की जानें चली जाती है। बड़े ठेकेदारों के डंपरों से ऊपर तक भरी हुई, मिट्टी रेत, गिट्टी, पत्थर, निगम, की गाड़ियों में ऊपर तक भरा हुआ कचरा, जो रास्ते पर पीछे आने या चलने वालों को दहशत देते हुए शहर भर में घूमते हैं। वो सबकुछ धनाघों को मिलते हुए महीने के कारण कुछ नहीं दिखता, निजी, मिनी बसों से लेकर अंतरनगरीय बसों में, नगर निगम और प्रशासन के सायें में चल रही अटल सिटी ट्रांसपोर्ट की बसों में न केवल ओवरलोडिंग, छेड़छाड़, ड्राइवर, कंडक्टरों का दुर्व्यवहार, दर से ज्यादा वसूली, लहराते हुए चलने, अनाधुंध भगाने, चाहे जहां रोककर सवारिया भरने उतारने के तांडव नहीं दिखते उन सब पर कार्यवाही की तो दूर उन्हें पुलिस, प्रशासन, परिवहन अधिकारी कोई नहीं रोकता क्योंकि महीना बंधा है। सबका, वे सब न केवल सभी प्रकार के तांडव करें, दुर्घटनाओं

हर अपराधी, भ्रष्टाचारी यही करता है, कमजोर कड़ी को दबाना मोटों से कमीशन खाना

में लोगों की जान ले लें। सब चलेगा, बसें, ट्रक, कारें, फर्जी नंबरों पर चले, परमिट निरस्ती, बिना परमिट के चले। डंपर चलाने वालो के पास लायसेंस तक नहीं होते, नगर निगम के 500 से ज्यादा वाहन चालकों के पास लायसेंस है कि नहीं इसका सत्यापन तक नहीं हुआ, यही हाल सरकारी वाहन जो किराये पर लिये जाते हैं। एक ही ठेकेदार टैक्सी परमिट की एक गाड़ी कई विभागों में लगाकर उसकी आड़ में निजी करों का जो कि टैक्सी कोटे में पंजीयन न होने के बाद भी अनेकों विभागों में पूरे प्रदेश में चल रही है। जिनके चालकों के पास वैध व्यावसायिक लाइसेंस तक नहीं होते है। अधिकांश विभागों में चल रही किराये की कारें वहीं के अधिकारियों और कर्मचारियों की है। पर सब मिल बांट खाने के आदि हैं। इसलिए सरकारी गाड़ियों के नाम चल रही किराये की गाड़ियों, उनके चालकों की कोई जांच नहीं होती, उनके चालक भी शाम होते ही शराब का सेवन कर गाड़ियां चला रहे हैं।

स्कूली ऑटों में जानवरों से बदतर हालातों में बच्चों को भरकर थानों के सामने से गुजर जाते हैं। क्या थानों के सीसीटीवी कैमरों में फोटो नहीं आते, चौराहों पर लगे कैमरों में दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट ही नजर आते हैं। खचाखच भरी बसें, ट्रक, मिनी बस, ऑटों फोन पर बात करते कार चालक, बिना नंबर की गाड़ियां के फोटो, नगर निगम के टैंकर, कचरे से भरी गाड़ियां पुलिस के वाहन, दिन में भारी वाहन नगर में घुमते हुए नजर नहीं आते या कैमरे उसकी फोटो ही नहीं लेते होंगे। शायद करोड़ों रुपए जनधन के बर्बाद केवल कमीशन खाने के लिए किए गए थे। उन सब सैकड़ों कैमरो की कार्यप्रणाली को थानों में, चौराहों पर जानबूझकर ठप्प और इसीलिए बिगाड़ा गया ताकि महीना देने वालों, माननीयों सरकारी गाड़ियों, अपने ही विभाग की पुलिस की गाड़ियों की कानून उल्लंघन पर बचाया जा सके। चौराहों पर जनधन से लगाये गए वैद्युतकीय पर्दो पर सारे दिन कार्टून दिखाये जाते रहते हैं। क्यों नहीं चौराहों पर लगे कैमरों की रिकार्डिंग सीधे ही उन वैद्युतकीय पर्दो पर दिखाई जाती। ताकि नियम तोड़ने वालें स्वयं शर्मिंदा होकर अनुशासन में चलकर स्वयं के साथ दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखें।

दूसरी तरफ नगर निगम सड़कों के रखरखाव के नमा पर क्या महापौर मालिनी गौड़ से लेकर नीचे, पार्षदों और आयुक्त से लेकर बाबुओं तक सब ठेकेदारों के माध्यम से मोटा कमीशन हजम करने ही बैठे हैं। अरबों रुपए, हर वर्ष सड़कों पर खर्च करने के नाम पहले रैलिंग फिर रैलिंग बेचकर पैसा हजम फिर कांक्रीट की दीवारें खड़ी करने और पैसा हजम करने में जो दोगुना चौगुना दरों पर काम करवाया जाता है न टैंडर बस चुपचाप चहेतों को काम। पैदल निकलने वालों को रास्ता तो दूर हर सड़क के कोने पर उसी सड़क के दूसरी ओर चौराहे पर जाकर मुड़ने की अपेक्षा पहले ही खुले हुए रास्ते को भी बंद कर दिया जाता है। जैसे सारे हरामखोर शूकरों की फौज पुलिस और नगर पालिकाओं, निगमों में बैठे सभी इंजिनियरों या इंजिनियरों की पैदाइश हो। अभी पिछले छह महीने से पूरे शहर की सड़कों के दोनों किनारों पर अच्छी लगी हुई ब्लॉक्स उखाड़कर नई लगाने का काम बड़े जोरों शोरों से जो लगभग एक अरब से ज्यादा का केवल गिद्ध पार्षदों और अधिकारियों कर्मचारियों की मोटी कमाई के लिए करवाया जा रहा है। सीमेंट की सड़कों पर डामरीकरण भी इसी नौच खसोंट का हिस्सा हैं, पर मुख्य सड़कों पर गड्ढे, टूट-फूट से कोई सरोकार नहीं। बस उनको दो पहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट क्यों नहीं क्यों ये नगर निगम के प्रशासन, पुलिस, परिवहन व अन्य विभागों के भ्रष्टाचार पर खुली आंखों और नंगे सिर उठाये दृष्टिपातकर अंगुली उठा रहा है। आम मध्यमवर्गीय बेचारा जो हर सरकारी और निजी लूट का शिकार होता है, सबके लिए सबसे कमजोर कड़ी है। ये ही सारे भ्रष्टाचारों, लूट के विरुद्ध आवाज उठाता है। इसलिए इसको हेलमेट पहनना जरूरी है। ताकि ये हेलमेट पहन घोड़ों की तरह सिर्फ सामने देखकर गाड़ी चलाये। इधर उधर ताकं झांक नहीं। भले ही आवाज न सुन पाने के कारण उसे कुछ सुनाई ही न पड़े, और पीछा वाला या दांये-बांये से निकलने वाला उसे ठोककर जान तक ले लें। पर व देख न सके। सैकड़ों हेलमेट लगाये दो पहिया वाहन चालक भी दुर्घटना की चपेट में आकर मर गये। इसी इंदौर में, जहां की सड़कों पर 40 किमी से ज्यादा गति से वाहन नहीं चलाये जा सकते है। क्षे.प. अधि. एमपी सिंग, जिलाधीश वरवड़े, आयुक्त संजय दुबे स्वयं दो पहिया वाहन पर बैठ हेलमेट लगा, 50-100 किमी शहर की सड़कों पर चल कर देखें। कदम-कदम छोटी सड़कों पर बने गति अवरोधक, अव्यवस्थित यातायात, कारों, मिनी बसों, ऑटों, छोटे वाहनों, मिनी ट्रक, लेंडिंग, वाहन चालकों की बतमीजियों में चारों तरफ निगाहें रख चलना कितना मुश्किल है। मालूम पड़ेगा। निसंदेह हर दो पहिया वाहन चालक सुरक्षा चाहता है। वाहन है तो हेलमेट भी उसके पास होना चाहिए, पंरतु लगाकर चलने में सिर पर भारी बोझ, सड़कों के गड्ढों और गति अवरोधकों के दचकों में सिर पर लगते झटकों से, लगाने के बाद होने वाली घुटन से परेशान हो, हेलमेट लगाना नहीं चाहता चालक।

● पूरे प्रदेश में दूध के नाम विष, सांची, अमूल के 32 वर्षों से नमूने नहीं ●

शासकीय सहकारी सांची और अमूल स्तरहीन, मिलावटी दूध

इंदौर। हाल में सांची, मांगलिया प्लांट के ठेके के टैंकर से दूध परिवहन और संग्रहण के बाद डेयरी में पहुंचाने के पहले ही सील तोड़कर अच्छा दूध निकालकर बाहर बेचने और उसमें रसायन और पानी मिलाकर टैंकर पहुंचाने के बड़े कांड को पुलिस ने पकड़ा। जिस लगातार सांची की इंदौर सहकारी दुग्ध संघ सारे समाचार पत्रों का मुंह बंद करने हर समाचार पत्र को लगातार चौथाई-2 पेज के विज्ञापन में अपनी सफाई पेश की, जो पूर्णतः निरर्थक थी, यथार्थ यह है कि पूरी मप्र की सारी दुग्ध सहकारी समीतियां और सहकारिता मंत्री से लेकर भोपाल स्थित इस के मुख्यालय तक सभी घोर जालसाज अधिकारी और कर्मचारी हर कदम पर भ्रष्टाचार का तांडव पिछले 40 वर्षों से कर रहे हैं। इसके साथ इनके चुने हुये अध्यक्ष व सदस्यों को यहां चुनकर आने का मतलब ही होता है कि ये चुने हुए इन समितियों, शासकीय कार्यालयों को लूट और चारागाह का अड्डा समझते हैं। इन्हें गाड़ी-घोड़े मिले, मुफ्त का रहवास, नौकर चाकर मिले, हर अंगूठे और हस्ताक्षर के बदले इन्हें नगद रोकड़ा मिले, इन्हे 90 प्रतिशत चुने हुओं को चाहे वो समीतियों, पंचायतों, नगर निगमों, पालिकाओं, विधानसभाओं और लोकसभाओं में बैठने और बोलने का सलीका हो न हो, फिर सहकार मिलकर करों बंटाधार, यह परम सूत्र है। सहकारिता का, तो यहां चुनकर आये अध्यक्षों और सदस्यों का हाल क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये ही है, जो परीक्षाओं से चयनित होकर आये कर्मचारियों, अधिकारियों, इंजिनियरों, विशेषज्ञों को दूध संग्रह के प्रबंध संचालकों को अपनी वसूली और भ्रष्टाचार के लिए मजबूर करते हैं और वे सब चयनित अधिकारी कर्मचारी इनकी लालसाओं को पूरा करने के लिए, स्तरहीन दूध, जिसमें कम वसा, कम क्रीम, कम चिकनाई या घी होता है। जनता को आपूर्ति करते हैं। यहां तक कि संभागीय स्तर पर बनी डेयरियों, संग्रहण व वितरण के केन्द्रों में बनी 8-10 डेयरियों

सारे चुने गये अध्यक्षों, सदस्यों से लेकर प्रदेश की सांची डेयरी के अधिकारी कर्मचारी घोर भ्रष्ट और जालसाज, जिलाधीश डांट देते हैं। खाद्य व औषधि विभाग के निरीक्षकों को और धमकाते हैं, स्थानांतरण व अन्य कार्यवाही के लिए, शुद्धता के लिए आवश्यक है, कि पूरे प्रदेश के निरीक्षक कहीं से कभी भी हर डेयरी के नमूने लें

केा यथा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा,भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सागर आदि में उपयोग की जाने वाली पॉलिथीन, थैलियों में स्तरहीन और कम मोटाई का पॉलिथीन उपयोग किया जाता है। जो 5 फिट ऊपर गिरने से फूट जाता है। जबकि अमूल गुजरात की थैलियों का स्तर इनसे ज्यादा मजबूत होता है। बेशक अमूल का दूध गुजरात से आता है, परंतु यहां की पैकिंग एजेंसी उसके स्तर को अपनी मोटी कमाई के चलते बिगाड़ देती है। जबकि 3-4 दिन पुराना दूध जिसे गुजरात से संग्रहित करने में पूरा दिन दो दिन लग जाते है, फिर प्लांट में जाने और भेजने में, पैकिंग कर उपभोक्ता तक पहुंचाने में 4-5 दिन पुराना दूध रसायनों के उपयोग से बचाकर ही उपभोक्ता का आपूर्ति की जाती है। इन सबके विपरीत विज्ञापनों में गाय का शुद्ध ताजा दूध लिखा जाता है, जो कि पूर्णतः भ्रामक और झूठ का पुलिंदा होता है। दूसरी तरफ सांची और अमूल दोनों की सरकारी सहकारी संस्थाएं टनों से दूध चूर्ण जो आस्ट्रेलिया, अजेन्टिना व अन्य राष्ट्रो से मंगाकर, उस दूध चूर्ण में पानी व अन्य रसायनों के साथ, मक्खन तेल मिलाकर, पेक किया जाकर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है। यथार्थ में मांग और आपूर्ति का ये अंतर इसी प्रकार की दूध आपूर्ति से पूरा किया जाता है। यह सच खाद्य एवं औषधि से बातों में उलझाकर जाना गया। साथ ही पिछले 10 वर्षों में इंदौर-उज्जैन के खाद्य निरीक्षकों से पूछा गया कि सांची और अमूल दूध के कितने नमूने लिए गए तो उनका साफ कहना था कि उनके दूध के नमूने लेने पर कलेक्टर उनका पदेन अध्यक्ष होता है। सीधे मोबाइल पर डांट पड़ती है कि नौकरी करना और यही रहना है कि नहीं। अमूल के नाम में भी गुजरात से फोन कलेक्टर के और उससे सीधा हमें आता है। इसलिए उसके नमूने लेने के हम पात्र नहीं। जब ये बात विधानसभा में उठाई गई तो शासन ने स्वीकार किया कि 1985 से कोई नमूने नहीं लिए गए। इन्हीं शासकीय सहकारी डेयरी के भ्रष्टाचार ने बाजार में रुपए 50-52 की दर कर दी, प्रति लीटर दूध की। जबकि ये दोनों ही गाय का शुद्ध प्राकृतिक दूध, ताजा दूध का विज्ञापन छापने वाले उसमें जीवाणुओं को नष्ट करने के वाले उसमें डीडीटी पाउडर तक मिला देते हैं। जिसकी बदबू कई बाद दूध की थैलियों से दूध निकालने के बाद आती मिलती है। इन जालसाजों ने सभी बड़े समाचार पत्रों को न केवल स्वयं विज्ञापन देकर मुंह बंद कर रखा है। वरन पत्रिका और भास्कर के विज्ञापन सांची के दूध व अन्य उत्पादों पर देखे जा सकते हैं। तू मेरी न छाप मैं तेरा विज्ञापन अपनी दूध की थैलियों पर कर दूंगा कि तर्ज पर इनका सच नहीं छापते। जबकि इन्हें शुद्ध गाय का प्राकृतिक ताजा दूध के विज्ञापन के आधार पर जनता को भ्रमित करने के 120 बी व 420 के आरोप में प्रकरण दर्ज करवाया जा सकता है।

साप्ताहिक समय माया

इंदौर इदिलाबाद 203 किमी सड़क हो गई बर्बाद

रा. राजमार्ग प्राधिकरण 10 वर्ष तक सड़क बनाने में, लेगा हजारों की जान

रा.रा. प्रा. का 10 वर्षों का इतिहास मप्र में बहुत ही शर्मनाक रहा, जब तक लो.नि.वि. रा.राजमार्ग को सौंपकर करों रखरखाव, पूरी सड़क हो गई खराब, दुर्घटनाओं में हो रही अकाल मौतें

इंदौर-एदलाबाद की 203 किमी दोहरी सड़क का अशोका बिल्डकॉन का 18 फरवरी 17 को ठेका समाप्त होने के बाद से पहले यह सड़क मप्र सड़क डकैती विकास निगम को सौंपी गई थी, जिसे तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया। अब उसके सर्वे की निविदा फिर सर्वे के बाद, फिर निर्माण की निविदा इसके बाद निर्माण की प्रक्रिया में 5 से 8 वर्ष लग जायेंगे तब तक बदहाल सड़कों पर लाखों वाहन टूट फूट के कारण बर्बाद हो चुकने के साथ हजारों लोगों की हड्डी पसली टूटने के और हजारों अकाल मृत्यु के शिकार होंगे। जैसा कि इंदौर अहमदाबाद, इंदौर शिवपुरा झांसी मार्ग पर हो रहा है। इंदौर खलघाट सेंधवा मार्ग ही ठीक-ठाक चल रहा है। अन्यथा प्रदेश के रा.रा. क्रमांक-59 इंदौर नेमावर भी रखरखाव के कार्य मप्र लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा ही संभाल रही जिससे चलने योग्य बना हुआ है। बेशक मप्र सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्र.स. प्रमोद अग्रवाल सचिव चं.प्र. अग्रवाल और प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल, अधिकतर कार्य जिसमें केन्द्रीय सड़क निधि मंडी निधि, एडीबी के अधिकांश कार्य, मप्र सड़क डकैती निगम को देना मोटे कमीशन के चलते ज्यादा देना पसंद करते हैं। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदौर सड़क डकैती निगम के का.य. या. संभागीय प्रबंधक बोरासी पिछले 8 वर्षों से यही जमाकर रख गया है। जिसके पास तीन पदों का प्रभार है। जानबूझकर यहां आंचलिक प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की गई, इस का प्रभार संभालने के साथ ही इंदौर 1-2 संभागों का संभागीय प्रबंधक भी है। आंचलिक प्रबंधक के रूप में इसके पास 14 जिलों का काम होने के साथ ही यहां भवन निर्माण कार्य आदि भी दिए जाने लगे हैं। 14 जिलों में मोटे महीने के चलते न तो पुरानी बीओटी की सड़कों पर और न ही किसी भी सड़क का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुसार करवाया जा रहा है। क्योंकि यह भ्रष्ट बोरासी सिविल इंजिनियरिंग का डिग्री धारी कार्य तो विशेषज्ञ बिलकुल नहीं जो खर्च किए धन का 70 प्रतिशत भी गुणवत्ता कार्य करवा सके। परंतु भ्रष्टाचार का विशेषज्ञ अवश्य हैं, जो खुलकर लेन-देन कर 7-8 वर्षों से जमा बैठा हुआ है।स्वाभाविक है कि ये इंदौर इदिलाबाद 203 किमी सड़क के दे दी जाये, वैसे यह भी सच है कि इसी लूटपाट के चलते भ्रष्ट, जालसाज, मु.मं. चौहान, मंत्री रामपाल सिंग, प्र.स., प्रमुख अभियंता ने लोक निर्माण विभाग की इस राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा को इस सड़क डकैती विकास निगम में मिला देने का निर्णय मई-जून से लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए थे, ताकि प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग 4600 किमी सड़कों के भा.रा.रा. वि प्राधिकरण से लेकर खुली लूट का तांडव कर सकें, जैसा कि मप्र सड़क डकैती निगम में चल रहा है।

जहां पर बीओटी 90 प्रतिशत ठेकेदार क्षेत्रीय, संभागीय प्रबंधक व प्रबंधनं से लेकर मुख्यालय तक महीना पहुंचाकर बिना सड़कों के उचित और आवश्यक रखरखावे के जनता को लूटकर और रखरखाव के खर्चे दिखाकर वह सारा माल अंदर कर रहे हैं। तो उन सड़कों पर लिए गए प्रदेश सरकार की जमानत के ऋणों की किश्तें भी अधिकांश ठेकेदार नहीं भर रहे हैं। इस दशा में स्वयं सरकार को ही जनाधन से बैंकों को देनदारियां चुकाना होंगी, फिर अगले दो वर्षों में चुनाव के चलते यह 203 किमी की सड़क मप्र लो.नि.वि. के राष्ट्रीय राजमार्ग को सुधार, पुर्ननिर्माण के लिए नहीं दी जाती है और इस सड़क मप्र लो.नि. वि. के राष्ट्रीय राजमार्ग को सुधार, पुर्नविभाग के लिए नहीं दी जाती हैं और इस सड़क के शीघ्र ही गड्ढे भराई और मरम्मत नहीं होती है। तो तीन जिलों के 15 से ज्यादा विधानसभा सीटें भाजपा के हाथ से जा सकती है। फिर मप्र सड़क वैसे ही हाल ही में अग्रवाल को हटा पुराने आजमगढ़िया सुलेमान को बैठा दिया गया। डकैती निगम की पूरे प्रदेश में जनता स लूट के बाद भी जो कि एकल, दोहरी सड़क पर पूर्ण अवैध होने के साथ ही चौहरी सड़क भी अच्छी सड़क जिस पर बिना दचके और उछलकूद के 80-90 किमी से तेज चला जा सके। मप्र लोक निर्माण विभाग की चांडाल अग्रवाल चौकड़ी जिसमें सचिव मु.मं. कार्यालय विवेक अग्रवाल भी शामिल है, बस लूट और मासिक पोश डकैती से ही काम है। कोई ऐसी सड़क नहीं।

कृषि विभाग- प्र.स. राजौरा से नीचे कृषि विस्तार अधिकारियों तक सब ही भ्रष्ट

खरीदी और वितरण में सब वसूल रहे मोटा कमीशन

ढेंचा और मिट्टी परीक्षण किट खरीदी में स्वयं राजोरा ने तो खाद बीज, किटनाशक में मुख्यालय से उप संचालक तक ने मोटा कमीशन बटोरा, उप संचालक विजय चौरसिया की भ्रष्टाचार की लंबी सूची, खरगोन, मुरैना के बाद इंदौर में भी तांडव शुरू, संयुक्त संचालक सिसोदिया अपील की तारीख देकर भगा देता है अपने चेले को

कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और लूट के तांडव में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, प्रधान सचिव से लेकर सचिव, संचालक से लेकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तक सब गहराई से धन बटोर रहे है। बदले में किसानों की फसल बिगाड़ने, कर्ज डूबने से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फिर भी भ्रष्ट शिवराज चिल्ला रहा है, शासन के 12 साल, बेमिसाल, मात्र 12000 से ज्यादा किसान मौत को गले लगा चुके हैं। फिर इस पर भी क्रीत कृषि कर्मणा पुरस्कार, जबकि नीचे से ऊपर तक हर कदम लूट पाट और भ्रष्टाचार के दम पर पिछले 4 वर्षों से ज्यादा समय कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में कुंडली मारे जमे बैठा है। दो उदाहरण देखिये जैविक खाद जो बाजार में रुपए 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बिना टेंडर प्रकाशित किए एक मात्र कं. जियोलाइट से 20000 टन खरीदा गया रुपए 125 प्रति कि. के भाव से, आदिवासी जिलों यथा धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर आदि में आदिवासियों को निःशुल्क बांटा गया। अनुसूचित जाति किसानों को 67 प्रतिशत और बाकी को 33 प्रतिशत व 50 प्रतिशत अनुदान पर खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अर्थात रुपए 200 करोड़ सीधे हजम बदले में रुपए 25-30 का माल 33 प्रतिशत और 50प्रतिशत के अनुदान पर भी बाजार से महंगा पड़ रहा है। दूसरा मृदा परीक्षण किट जो बाजार में रुपए

5000 की है, रुपए 1,05,000 में 10000 किट खरीद कर हर भूमि कृषि विस्तार अधिकारी को 4 से 5 किट टिका दी गई। ऐसे अनेकों सामग्री जिसके खाद बीज, कीटनाशक, खरपतनाशक व अन्य सामग्री जिसमें अरबों रुपए खर्च होता है दोगुनी दरों से लेकर 10-20 गुनी कीमत में खरीदी कर किसानों को खरीदने पर मजबूर किया जाकर अरबों रुपए का मोटा कमीशन हजम किया जाता है।दूसरी तरफ प्रशासकीय भ्रष्ट कार्यप्रणाली से राजेश राजोरा भारी मोटी कमाई निलंबन करना निलंबन समाप्त करने, मनचाही पदस्थापना देने में भी राजोरा का कोई सानी नहीं, पूर्व में 5 उपसंचालकों के निलंबन के बाद मोटी वसूली कर उन्हें संयुक्त संचालन के पद पर आरुढ़ करने के बारे में बताया था जिसमें एक इंदौश्र में पदस्थ रेवा सिंग सिसौदिया जो खरगोन से निलंबित हुऐ मोटा धन वसूलकर इन्हें इंदौर का संयुक्त संचालक कृषि बना दिया गया। इसके साथ ही इनके चेले या अधीनस्थ रहे भूमि संरक्षण अधिकारी विजय चौरसिया को जिन्होंने अनेकों भ्रष्टाचार किए इनके भी अनेकों तालाब चोरी हो गए, किसानों को बलराम तालाब और खेत का पानी खेत में की योजनाओं का अनुदान जो लगभग 3000 तालाबों में 1800 तालाबों में स्तरहीन तालाब बनाकर पैसा हजम कर लिया गया, ऐसे अनेकों आरोपों में विजय चौरसिया को निलंबित किया गया पर राजेश राजौरा ने मोटा धन हड़प कर तत्काल निलंबन वापिस लेकर पदोन्नति देते हुए मुरैना का उप संचालक बना दिया। वहां भी चौरसिया ने भारी भ्रष्टाचार किया पुनः निलंबन किया परंतु यहां भी वही इतिहास दुहराया गया, पुनः मोटी धन राशि लेकर इंदौर का का उपसंचालक बना दिया गया। चौरसिया ने यहां पर भी आते ही जालसाजियां और भ्रष्टाचार का तांडव करना शुरू कर दिया। पहले क्रम में आते ही उन्होंने बीज, खाद के नमूनों के नाम पर लाखों वसूले अपनी इच्छानुसार भ्रष्ट कर्मचारियों को जो देपालपुर सांवेर में पदस्थ थे। उनको इंदौर संलग्न किया। स्वाभाविक जानकारी मिलते ही समय माया डॉट कॉम की साइट पर कहानी चढ़ाई गई। शिकायतों और पुराने कुकर्मों के चलते पुनः नवम्बर में चौरसिया का स्थानांतरण कर दिया गया, यही हाल देवास में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर 19 वर्ष गुजार देने वाले आलोक मीणा का भी हुआ, उन्होंने चौरसिया की तरह अपनी मनचाही और मोटा कमीशन बांटने वाली फर्मों, संभाल खरीदकर ग्रामीण समीतियों में पहुंचाकर कृषकों पर थोपा, जबकि कृषकों को माल यथा खाद, बीज, कीटनाशक खरीदने की छूट है और उनमें बिलों पर अनुदान उनके खाते में भेजा जाता है। वैसे यह कहानी केवल इंदौर-उज्जैन संभाग के 15 जिलों की ही नहीं वरन पूरे मप्र की है।

सफाई के नाम जनता से की जा रही मोटी लुटाई

सफाई के नाम महापौर, आयुक्त, पार्षद, पंच व अन्य कर रहे मोटी कमाई

वाहन, उपकरणों आदि की खरीद में मोटा कमीशन, डीजल, पेट्रोल 70 प्रतिशत झूठे बिलों से लूट पर सफाई कर्मियों का तन, मन, धन से हो रहा शोषण 30 से 50 प्रतिशत फर्जी वेतन

2006 में परियोजना उदय में आये 100 से ज्यादा आये अलग किस्म के ट्रक, 5000 से ज्यादा रिक्शे 2000 से ज्यादा हाथ गाड़ियां व अरब रुपए का अन्य सामान कहां गायब हो गया,बिना उपयोग

मोदी ने विदेश यात्राओं में रुपए 50 लाख करोड़ से ज्यादा फूंके, जब आक्रोश ज्यादा उपजने लगा तो सब को झाड़ू पकड़ा दी। स्वयं झाड़ू पकड़ गंदी बस्तियों मे पहुंच न केवल सफाई करने पहुंच गया, वरन जिन लोगों को जन-धन से लाखों रुपए हर माह वेतन दिया जा रहा था। उनसे उनका मूल कार्य छुड़वा झाड़ू थमा, सड़कों पर नौटंकी थमाने खड़ा कर दिया। जैसे मोदी के आने के केवल बेहूदी और बत्तमीजीपूर्ण शब्दों और वाक्यों की प्रचार प्रस्तुति पर ही खर्च कर जिसमें टीवी चैनलों पर विज्ञापन से लेकर मुद्रित दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं पर खर्च करने के नियमों के विपरीत जाकर सफाई के विज्ञापन पूरे देश 65000 से ज्यादा पंचायतों से लेकर 5000 कस्बों, 3000 से ज्यादा विकास खंडों, 860 जिला मुख्यालयों, 20 ज्यादा महानगरों में बर्बाद किया गया। कभी स्वास्थ्य मद, नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास व पंचायत मद, भूतल परिवहन, पेट्रोलिय व अन्य अनेकों मंत्रालय से खर्च करवाया गया बदले में 0.5 प्रतिशत का शुल्क वसूली सेस के रूप में पेट्रोल, डीजल, ईंधन, वायु, विद्युत, बिलों व अन्य सेवा करों के रूप में जनता पर ठोंकने और वसूलने के बाद भी चैन नहीं पड़ा तो हर घर से रुपए 60 से लेकर दुकानों से 200 प्रतिमाह की अलग से वसूली कर सरपंचों, पार्षदों, सफाईकर्मियों, दरोगाओं, पर्यवेक्षकों, सबकी अंट-शंट लूट और कमाई के तरीके खोल हजारों से करोड़ों रुपए प्रतिमाह कमाई के नए रास्ते खोल दिये, जबकि 70 प्रतिशत सफाईकर्मियों के नाम से निकलने वाला वेतन फर्जी सफाईकर्मियों के नाम से हर माह निकाल पंच-सरपंचों से लेकर पार्षदों, महापौरों, बाबुओं, कर्मचारियों, अधिकारियों, उपायुक्तों, आयुक्तों, पंचायत, जनपद सचिवों तक सबको अरबों की लूट के रास्ते आसान कर दिये, नगरी निकाय स्तर पर ट्रकों, मिनी ट्रकों, जीपों की खरीद में, गीले सूखे कचरे के डिब्बों में जो हर चौराहों पर लोहे के स्टेंडों के साथ पूरे प्रदेश के हर निगमों और पालिकाओं ने लगाये, में भी अरबों रुपए का भारी भ्रष्टाचार कर सबने मिल बांटकर हजम किया। साथ ही कई बार कचरे के डिब्बों को घरों में बांटने से लेकर चौराहों पर लगाने के बाद गायब कर दिए गए। हर शहर, पंचायत, तहसील को नंबर 1 का खिताब बांटा गया, उसके नाम पर विज्ञापन में ही, इस लूट खसोंट को कोई न छापे, समाचार पत्रों, चैनलों की खूब जन-धन लुटाया गया।

वैसे भी नगर निगमों, पालिकाओं चाहे वे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर से लेकर जिलों तहसीलों और पंचायतों तक में सफाई के नाम अंधे पीसें कुत्ते खये के नाम पर कर्मचारियों को वेतन न बांटने, सफाई हेतु झाड़ुओं से लेकर गाड़ियों, उनकी मरम्मत, तेल डीजल, पेट्रोल, क्लोरीन, फिनाइल व अन्य सहस्त्रों सामग्री की खरीद वितरण पर कोई प्रभावी नियंत्रण देखरेख के साथ इन सभी का हर महीने महालेखाकार से अंकेक्षण करवाया जाना चाहिए। स्टॉक, वाहनों, उपयोग की गई सामग्री का सत्यापन और देखरेख की ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए। पिछले 17 वर्षों में अरबों रुपए के वाहन खरीदे गए। सन् 2006-07 प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत एशियन विकास बैंक से खरीदे गए पंप गाड़ियां, कचरों के बड़े टैंकरों, को लोडकर ले जाने वाले ट्रक आदि भारी संख्या में खरीदी इंदौर के मूसाखेड़ी के जलप्रदाय केन्द्रों में रखे थे। सालों तक पड़े रहने के बाद धीरे-धीरे सब गायब हो गये, कहां उपयोग हुआ मालूम नहीं। सफाई के नाम पर नगरों में छोटे व्यापारियें ठेले वालों पर पॉलिथीन के उपयोग पर अमानक बताकर प्रतिबंध लगाया वही सरकारी सांची डेयरी का दूध भी अमानक पॉलीथीन में ही बिक रहा है। इसके साथ सबसे ज्यादा पैकिंग का कचरा बहुराष्ट्रीय कं. की पैकिंग फैला रही है। चाहे वो एल्युमीनियम की पन्नियां हों या पॉलीथिन पर उन पर अभी तक प्रतिबंध लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि छोटों को हड़काकर बड़ों से मोटा कमीशन सभी को मिलता है। फिर सफाई के नाम पर नगर निगम की कचरा गाड़ियां जो ध्वनि प्रदूषण से सबको परेशान कर उन पर कौन रोक लगाएगा।

इंदौर के ही सघन बाजारों जैसे महारानी रोड, मारोठिया, राजवाड़ा आदि सैकड़ों स्थानों पर निगम ने मूत्रालयों आदि की 50 वर्ष बाद भी व्यवस्था नहीं की जबकि वहां के व्यापारी, कर्मचारी, ग्राहक आदि मूत्र वेग से राहत पाने के लिए दबे छुपे स्थानों पर प्रयास करते पाये जाने पर निगम के सफाई निरीक्षकों ने पहले मूत्रालयों की स्थापना में तो तो कोई प्रयास नहीं किया परंतु ऐसे मूत्र वेग से पीड़ितों का लगातार 6 महीने फर्जी रसीदों पर चालान बनाकर रुपए 100 से 500 की प्रति व्यक्ति अवश्य कर रहे है। वे गिद्ध बतायें कि 50 वर्षों में शासन और निगम ने विक्रय कर इंट्री टैक्स के नाम व्यापारियों से अरबों रुपए वसूलने के बाद भी मूत्रालय नहीं बनवा पाये तो आम जन को प्रताड़ित कर वसूली क्यों कर रहे हैं।

रेलवे के निजीकरण के लिए सुनियोजित षड़यंत्र

रेलवे में जानबूझकर करवाई जा रही दुर्घटनायें, ताकि सौंप सके पूंजीपतियों को

नहीं किया जा रहा मरम्मत और उचित रखरखाव, इंजीनियरों की, गैंग स्टॉफ, की लाखों भर्तियां, रेलवे मंडल में भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारियों को बैठाने की तैयारी, रेल गरीबों के लिए नहीं, मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट में 8 से 12 आरक्षित 8 से 10 एसी, सामान्य के लिए 1-2, 99 प्रतिशत माल व यात्री वाहक डिब्बे समय बाधितों की मरम्मत भी नहीं

भारतीय रेलवे में आए दिन जो दुर्घनायें हो रही हैं, तो पूर्णतः प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में चल रहा पूर्व सुनियोजित षड़यंत्र है, जिसके अंतर्गत समय बाधित रेल के डीजल और विद्युत इंजिनों यात्री व माल वाहक की जो कि पूर्णतः समय बाधित और तय मापदण्डों से तिगुनी चौगुनी सेवायें दे चुके हैं। कि कलपूर्जों और आवश्यक सामग्री की जानबूझकर समय पर खरीदी न किए जाने, दूसरी तरफ वर्कशॉप्स व लोको व वेगन शेड में पर्याप्त इंजीनियरों, तकनीकी वायरमेन, फिटर, वेल्डर आदि की भर्तीयां सालों से न किए जाने के कारण स्टॉफ के घोर अभाव में न तो पटरियों पर दौड़ रहे इंजिनों, यात्री व माल वाहक वैगनों का ढंग से पर्याप्त व उचित रखरखाव किया व करवाया जा रहा है और बिगड़े हुए डीजल व विद्युत इंजिनों का पर्याप्त व उचित समुचित मरम्मत व सुधार कार्य किया जा रहा है। वही हाल पुरानी पटरियों के समय पर बदलने और सुधार कार्य सामग्री और इंजिनियरों व गैंगमैनों की स्थाई भर्तियों के अभाव में किया जा सक रहा है। जबकि रेल यात्रियों से 2013 के मुकाबले रुपए 5 के प्लेटफार्म टिकिट के बदले रुपए 30-40, 10 का टिकट के जुर्माने के वसूले जा रहे हैं कि एक यात्री सामान्य डिब्बे का टिकट लेकर जगह न होने से आरक्षित वर्ग के डिब्बे में जाकर मात्र खड़ा हो गया। इस शूकर ने रुपए 450 चंद घंटे की यात्रा के रुपए 450 वसूले। अर्थात दुनिया का कौन सा कानून है जहां मूल किराये की तिगुनी चौगुने दंड की राशि। हरामखोरों ने एक तरफ आमजन को परेशान करने के लिए एक तो सामान्य वर्ग के लिए पूरी रेल के 24 डिब्बों में 12 कोच नहीं लगाये। बैठने की व्यवस्था नहीं दी 24 कोच की ट्रेन में 12 डिब्बे आरक्षित, 10 डिब्बे वातानुकूलित, 1 डिब्बा सामान्य वर्ग का, 1 डिब्बे का आधा महिलाओं का और आधा दिव्यांगों, जिसके 22 आरक्षित और उच्च श्रेणी की शाखिकाओं पर रेलवे कर्मचारियों और उनके दलालों का कब्जा, तो आम आदमी क्या उच्च दाब वाली विद्युत लाइनों के नीचे मौत को दावत देता हुआ डिब्बों पर यात्रा करें। इसके साथ ही फिरे डिब्बे के नीचे लगे पहियों टूटे हुए एक्सलों, बियरिंग्स जो वर्षों से तल पानी आदि के रखरखाव होने और संयुक्तिकरण ढंग से न किये जाने की आवाजें यात्रियों को भयभीत करती है। शौचालयों में पश्चिमी और देशी में सुधार न होने से यात्रियों की बैठने में तकलीफें, जलाभाव, वातानुकूलित डिब्बों में बदबू मारती चादरें, कंबल, तकिये आदि। रेलवे में हर कदम लूट, भ्रष्टाचार का भारी बोलबाला है। फिर नेताओं, मंत्रियों के रिश्तेदारों को पिछले व सामने के दरवाजे से मोटे कमीशन पर सफाई से लेकर स्टेशनों तक को नीलाम कर ठेके पर दिया जा रहा है। ये सारे ठेके नेताओं, मंत्रियों के खास पूंजीपतियों को बांटे जा रहे हैं। बदले में मोटा कमीशन और मोटा भुगतान कर पूरे देश में हर महीने अरबों रुपए की लुटाई की और करवाई जा रही है। इस लूट की आड़ में लगातार किराया बढ़ाया जा रहा है। सामान्य श्रेणी के रुपए 150 के टिकिट पर आरक्षित डिब्बे में पैर रखने के भी रुपए 450 का दंड वसूला जा रहा है। रुपए 3 का प्लेटफार्म जो 70 वर्ष में 5 पैसे का था, रुपए 3 से 5 साल में सीधा रुपए 10 हो गया और त्यौहारों पर रुपए 20 करके लूटा जा रहा है। जनता के पैसे से बने रेलवे स्टेशनों को मोटे कमीशन हजम कर मोदी सरकार के गिद्धों ने पूंजीपतियों को न केवल जनता को प्लेटफार्म टिकट जो अभी रुपए 10-20 का हुआ है, फिर रुपए 10 प्रति घंटे के हिसाब से ही मिलेगा, जब निजी हाथों में जायेंगे तो वहां यात्रियों से हर तरह से पानी से लेकर चाय, दूध, भोजन आदि में चौगुनी वसूली, महिलाओं से ठेकेदारों के गुंडे ही लूट पाट और छेड़छाड़ करेंगे, चूंकि पुलिस को महीना मिलेगा तो वो चुप बैठी रहेगी, बेशक जिम्मेदारों को महीना बांटकर दूध के स्थान पर हर छोटे-बड़े स्टेशनों पर चलती रेलों में सफेद और रसायनों से बने चाय काफी से क्रीम की मिठास में पिछले 30 वर्षों से पिलाई जा रही है। यह सब जानकर भी खाद्य निरीक्षक से हर महीने मोटी वसूली कर बैठा है। दूसरी और भारतीय रेलवे पर्यटन नि. के अधिकारी, संभागीय, सामान्य रेल प्रबंधक सब जानकर और मोटी वसूली कर चुप बैठे है।

दूसरी ओर रेलवे गैंगमेन से लेकर निरीक्षक रेलवे ट्रेक इंजीनियरों की घोर कर्मा और भर्ती के अभाव में साथ ही धन की अपर्याप्तता के चलते, न तो वरिष्ठों की फौज ढंग से रेलवे के स्थापित मापदंडों के अनुसार रखरखाव कर रही है। न ही नई रेल लाइनों के निश्चित समयानुसार बिछाने का काम किया जा रहा है। इन सबके पीछे घोर भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ोत्री से ज्यादा कमीशन और जानबूझकर दुर्घटनाओं को अंजाम देकर रेलवे की वर्तमान कार्यप्रणाली को बदनाम करना और दहशत फैलाकर आसानी से निजीकरण की तरफ धकेल अपने बापों अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला व अन्य को सार्वजनिक संपत्तियों के मोटे कमीशन पर हस्तांतरण की स्पष्ट साजिश है। जो पहले ये देशी पूंजीपतियों के हाथ में जायेंगी फिर धीर-धीरे विदेशी कंपनियों को हस्तांतरित कर दी जायेंगी जैसा कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात विश्व व्यापारिक शोषण संगठन में बैठे धूर्त गिद्धों ने अनेकों देशों में किया।

इस धूर्त अशिक्षित मोदी को 130 करोड़ लोगों के वर्तमान और भविष्य से कोई मतलब नहीं जैसे ये दानवीय प्रवृत्ति का अमर फल खाकर आए हो, इसलिए रेलवे जैसे सार्वजनिक धन से निर्मित और संचालित पूरे संस्थान को बर्बाद करने पर तुला है, जबकि हर कदम पर रेलवे में सेवाओं की दरें बढ़ाने के बाद भी, हर दिन सैंकड़ों रेले चटकी और टूटी पटरियों से जानबूझकर रखरखाव और मरम्मत कार्य न करके लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।

इन सबके विपरीत अपने आपका नाम मृत्यु के बाद भी चलता रहे, युग पुरुष बनने के लिए अहमदाबाद से मुंबई तक रुपए 1 लाख करोड़ में 550 किमी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अहमदाबाद में उदघाटन करवा लिया गया है। जबकि रुपए 1800 करोड़ प्रति किमी की लागत वाली इस रेल की डीपीआर ही दोगुनी कीमत बना कर दिखाई गई है।, जबकि भारत में इस परियोजना में लगने वाला लोहा मात्र रुपए 40, 000 प्रति टन ही है। और सीमेंट भी रुपए 6000 प्रति टन है। अर्थात रुपए 70-80 प्रति किमी की लागत को औसत रुपए 18 करोड़ प्रति किमी दिखाया गया। दूसरी तरफ बन जाने के बाद दुगना ब्याज चुकायेगी जनता के पैसे से सरकार और ट्रेन चलायेगा अंबानी, जिसके दो फेरे लगाने के बाद रुपए 2000 करोड़ की किश्त और ब्याज दरों रुपए 4000 करोड़ फिर भारत की लेटलतीफी की आदत के चलते रुपए 1 लाख करोड़ की योजना रुपए डेढ़ लाख करोड़ की महंगाई बढ़ने से जब ये हरामखोर जालसाज मुखेराजन पार्टी के लोग नेता मंत्री अच्छे खासे शताब्दी पुरानी जमी जमाई व्यवस्था को कमीशनखोरी के चलते तबाह करने पर तुले रहकर जान बूझकर पूरे देश में उचित रखरखाव व मरम्मत न कर, दुर्घटनाओं से हजारों आदमियों की मौत बन रहे हैं। वो कल उस बुलेट ट्रेन की क्या हालत होगी, फिर बुलेट ट्रेन का तीन घंटे का किराया विमान यात्रा के किराये से जो मात्र एक घंटे में अहमदाबाद से दिल्ली और डेढ़ घंटे में बंबई पहुंचा देता है। तो क्या बुलेट ट्रेन केवल नेताओं और मंत्रियों के लिए चलाई जाएगी।

अक्ल के दुश्मन गुजरात के चुनाव जीतने के लिए बुलेट ट्रेन से ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान में रेलवे के घोषणा के अनुकूल 10 लाख भर्तियां व केन्द्र व राज्य शासन में आवश्यक 50 लाख भर्तियां कर रोजगार देकर रेलवे को नोंचने खाने की अपेक्षा उसे आधारभूत ढांचे को मजबूत कर सामान्य पैसेंजर ट्रेन की गति को न्यूनतम 60 किमी प्रति घंटा और एक्सप्रेस की 100 व सुपर फास्ट की गति को 150 किमी प्रति घंटे की गति देते। नई विद्युतीकृत लाइनें बिछाने, नोंचने, खाने, भ्रष्टाचार मिटाते।

मप्र वाणिज्यकर- जीएसटी लगने से मायूस है पूरा विभाग

सूचना अधिकार में जानकारी देने से बचने, उपायुक्त ही बनाये अपीलीय अधिकारी

निहायत ढीले आयुक्त की विदाई आवश्यक, बंद करो वाहन सुविधायें, संयुक्त आयुक्तों तक की, बंद करो एंटी इवेजन, एलटीगु, ऑडिट और अपील उपायुक्तों के पद

मप्र वाणिज्य कर में जबसे जीएसटी लगा है, 90 प्रतिशत काम समाप्त हो चुका है, माल व सेवा कर, संक्षिप्त रूप मसक ने करदाताओं को ही नहीं मसका वरन पूरा कर विभाग को मसक कर मुर्दा बना दिया है। पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. के लाभ और छोटे व्यापारियों उत्पादकों और व्यवसायियों को कर की उल्टी सीधी व्याख्याओं और ब्लिष्टता में उलझाकर समाप्ति की ओर धकेल बड़े व्यावसायियों और पूंजीपतियों को प्रतिस्पर्धियों को समाप्त कर निर्द्धन्द लूट की खुली छूट की कोशिश की है। जो असफल होने के कारण स्वयं सरकार को बार-बार संसोधनों और दरों को घटाने के लिए विवश कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि इस ब्लिष्टता और कानूनी स्पष्ट व्याख्या के अभाव में पूरे कर्मचारी अधिकारियों से लेकर स्वयं सरकार भी उलझी हुई है। वित्त मंत्री अरुण चीटली से लेकर, केन्द्र के कर विभाग के प्रधान सचिव, सचिवों से लेकर राज्यों के करायुक्त ही स्वयं ही पूरी तरह से इस क्लिष्ट कर संग्रहण की प्रणाली को समझने में और कर संग्रहण प्रणाली की स्पष्ट व्याख्या करने में असफल रहे हैं। तो फिर करदाता को धमका, दंड वसूली का प्रावधान कर उससे किस आधार पर वसूला जा रहा है। इस यक्ष प्रश्न का उत्तर कौन देगा। बेशक यह अर्थशास्त्र की कर प्रणाली के नियमों के बिलकुल विपरीत और धूर्त पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है, वे एक तरफ जनता से मनमाना कर वसूल रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनके महाधूर्त सनदी लेखाकारों और कानूनी कर सलाहकारों का समूह उन क्लिष्ट कानूनों उसकी धाराओं,बंधों और उपबंधों की व्याख्या अपने तरह से कर, भारी कर चोरी करने में कामयाब रहेगा जैसा कि हमारे देश में इस मसक को लगने से पूर्व पूरी दुनिया के 165 देशों में लागू इस मसक के परिणाम सामने आये, यथार्थ युरोपीय धूर्त बहुराष्ट्रीय कं. ने इस कर को अपने लाभ के लिए और छोटे व्यापारी, व्यावसायियों,उत्पादकों को समाप्त कर, प्रतिस्पर्धा समाप्त करने सभी देशों की सरकारों को अरबों करोड़ डॉलर देकर, इस तरह से कूटरचित इस कानून को लागू करवाया है। फिर हमारे देश की सत्ता में बैठे भुखेरों की फौज जो घोर लालची और मूढ गिद्धों की टोली के बिना आगे पीछे राष्ट्र व जनहित के बारे में सोचे समझे पूरे देश को नोंच खाने के लिए कुख्यात है कि उसे देश के भले बुरे से कोई मतलब ही नहीं होता चाहे वह मुखेरा जन पार्टी हो या कांग्रेस दोनों का पूंजीपतियों के इशारे पर नाच उनसे मोटा कमीशन वसूल कर जनता का शोषण करना ही है। मसक इस का प्रत्यक्ष उदाहरण है।मप्र के वाणिज्य कर विभाग में मसक लगने के बाद से सारा कार्य संचार जाल पर जाने से विभाग में वेट की अपेक्षा 10 प्रतिशत भी कार्य नए मसक का नहीं है, तो फिर वसूली और जांच का कार्य ही बंद है, तो यहां के राज्यकर अधिकारियों, सहाकर आयुक्तों, उपायुक्तों को वाहन सुविधा पर अनावश्यक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पर कार्यालय से घर तक जाने के लिए जब 7वां वेतनमान में मोटा वेतन मिलने ही लगा है साथ ही महा नगर भत्ता मिलता है, वाहनों की उपलब्धता केवल आयुक्त, अपर आयुक्तों तक तो ठीक है, इस पर अनावश्यक खर्च का कोई औचित्य नहीं। फिर शासन भी मिलव्यतिता की तरफ ध्यान दे रहा है तो राज्य कराअधिकारियों, सहायक आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों की टैक्सी व्यवस्था पर खर्च हो रही रुपए 1 करोड़ से ज्यादा खर्च को आसानी से बचाया जाना चाहिए। आयुक्त राघवेन्द्र सिंह ने अपने कार्यकाल में सूचना के अधिकार को पूर्णतः निरर्थक किया जा रहा है। अधिनियम में स्पष्ट व्याख्या है कि विभाग प्रमुख लोक सूचना अधिकारी और उसका वरिष्ठ अधिकारी अपीलीय अधिकारी होना चाहिए। पर यहां तो मुख्यालय में भी मात्र कर अधिकारी लोक सूचना अधिकारी और सहायक आयुक्त को अपीलीय

अधिकारी बनाकर जालसाज आयुक्त ने अपर आयुक्त के अधिकारी को बचाया गया वहीं उपायुक्तों के कार्यालयों सहायक आयुक्तों को लोक सूचना अधिकारी और उपायुक्त को अपीलीय अधिकारी बना कानून और जनता पर बड़ा अहसान किया अन्यथा हरामखोर चपरासी बाबू और लोक सूचना अधिकारी और बड़े बाबू को अपीलीय अधिकारी भी बना, जानकारी न मिलने या आयोग के दंड पर उसके गले में घंटी बांध जानकारी न देने निलंबन और सेवा समाप्ति का तोहफा भी दे सकते थे। जबकि पूर्व में उपायुक्त अपने कार्यालयों का लोक सूचना अधिकारी और अपर आयुक्त उसका अपीलीय व अधिकारी होता था। पर जालसाजों ने बचने के सारी व्यवस्थाएं बदल दी।

चुन-चुन कर भ्रष्टों जालसाजों कों बैठाया जाता है विद्युत कं. मप्र में

चारों तरफ विद्युत कं. में लूट और जालसाजी का तांडव

मप्र की बिजली का दिल्ली में 200 यूनिट का रु. 450 और मप्र में 200 यूनिट के रु. 1400 से 3000 तक की लूट, फिर शून्य या कनेक्शन कटे होने पर भी रुपए 2000-3000 तक के बिल

मुख्यमंत्री ऑनलाइन की नौटंकी में विद्युत की पुलिस की शिकायतें सुनना भी बंद। सूचना अधिकार में जानकारी देने में भी भारी नौटंकी और परेशान करते है। आवेदकों को मप्र में विद्युत कंपनी की लूट की भारी जालसाजियों, मनचाही रीडिंग, मनचाहे बिलों की हजारों शिकायतों पर सुनवाई की अपेक्षा यहां बैठे मीटर रीडरों, जो ठेके पर नौकरी करते हुए वर्षों से एक ही वितरण केन्द्रों पर जमे हैं। जो मुट्ठी गर्म करें उनकी बात माने उन्हें लूट और जो मुट्ठी गर्म न करे उनसे मनमानी रीडिंग चाहे वो शून्य ही क्यों न हो मनमानी यूनिट की बिलिंग करवाते हैं। फिर ऐसे में उपकेन्द्रों पर बैठे उपयंत्री, सहायक यंत्री की घोर बत्तमीजी हरामखोर जालसाजों की फौज बिलों की शिकायत करने वालों को न तो ढंग से सुनती है, उल्टे ही उन्हें हड़का और डांट डपट कर ज्यादा अनुनय विनय करने पर ये गिद्धों की फौज बिलों को टुकड़ों में जमा करने के लिए कहेगी। जब कनेक्शन काट दिया, मीटर के रुपए 200 के 1200 रुपए जमा करवाकर मीटर लगाया तो फिर काहे का मीटर का किराया और काहे का बिल। प्रदेश के अधिकांश झोनों पर यही बत्तमीजों की फौज उसकी झोपड़ी में ताला लगा देगी। सांयकल,मोटर साइकिल जब्त कर लेगी। ऊपर से प्रदेश का मुख्यमंत्री घोर जालसाज शिवराज घोषणा करेगा कि गरीबों के बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। जैसे हरामखोर जनता पर एहसान कर रहे है। प्रदेश में साढ़े नो हजार मेवा की खपत के विपरीत उत्पादन 25000 मेवा से ज्यादा होने के बाद भी प्रदेश के न केवल गावों में वरन इंदौर जैसे शहरों की आंख मिचौली चलती रहती है। गांवों में मात्र 10-12 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। एक तरफ दूसरे प्रदेशों को सस्ती रुपए 2 से 3 प्रति युनिट की बिजली बेंची जाती है। तो दूसरी तरफ लगभग 10 हजार से ज्यादा मे.वा. विद्युत रुपए 2 से 3 प्रति युनिट के कमीशन पर टाटा, रिलायंस, पॉवर की ताप और दूसरी अन्य कं. से सौर पवन विद्युत जिसकी उत्पादन लागत शून्य है। पर पूंजीगत लागत के ब्याज व अन्य खर्चों को भी मिला दिया जाए तो 25 से 30 पै. यूनिट बिजली साढ़े पांच रुपए में खरीदी जा रही है। जब कि अपने हिस्से की राजवि नि.की इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर की पूर्वाधिकार की 49 प्रतिशत विद्युत नहीं खरीदी जा रही है। सिंगाजी के नए ताप विद्युत गृह के साथ, जानबूझकर सारणी, विरसिंगपुर पाली के पुराने ताप विद्युत गृहों को जानबूझकर न्यूनतम पर चलाया जा रहा है। पुराने ताप विद्युत गृहों को तो बंद करने का भी षड़यंत्र रच कबाड़े में बेचने की भी पूरी तैयारी है। एक तरफ अपने हिस्से की बिजनी न खरीदना, ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों की षड़यंत्र पूर्व बर्बाद करना, दूसरी तरफ निजी उत्पादकों से 50 से 70 प्रश कमीशन पर ऊंचे भावों में बिजली खरीद दूसरे राज्यों को सस्ते में बेंचना, फिर प्रदेश के उपभोक्ताओं को दोगुने से 10 गुने तेज मीटर हर साल में 2 बार कीमतों में बढ़ोत्री कर जनता को लूट, वितरण कं. में बैठाये गये अपने महाधूर्त भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों जैसे इंदौर में आकाश त्रिपाठी, जैसे घोर भ्रष्ट और जालसाज को जिसने भाजपा की ईवीएम की जालसाजी के साथ मनगढ़त गिनती से जितवाकर सत्ता सौंपी थी उसके पुरुस्कार स्वरूप उसे इस वितरण कं. में जिसे विद्युत की वोल्टेज, एंपीयर, युनिट, मे. वाट किलो वाट तक का अ ब स द नहीं आता केवल लूटने बैठा दिया गया। साथ ही फिर घोर भ्रष्ट जालसाज सुब्रतो राय की सेवानिवृत्ति से पहले लोकायुक्त इसकी संपत्ति की जांच करें, तो मालूम पड़ेगा कि इसकी कार्यशैली क्या है। एक तरफ चोरों को स्वयं विभाग के बड़े अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं, मोटा धन वसूल रहे हैं। तो दूसरी कमजोरों को जिनके पास 50 यूनिट भी माह की खपत नहीं हजारों लाखों के बिल देकर धमकाया चमकाया जा रहा है। जबकि प्रदेश के मुख्यालय कंपनियों के मुख्यालयों से संभागीय कार्यालयों वितरण केन्द्रों पर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हरामखोरों और जालसाजों की फौज सारे बहाने गिनायेगी। अपील लगाने पर बड़े वकीलों को खड़ा करेगी हजारों रुपए बर्बाद करेगी पर जानकारी नहीं देगी। फिर जनता ईंट का जवाब पत्थर से देती है। तो पुलिस को मोटा पैसा खिलाकर रिपोर्ट लिखवाना न्यायालयों में प्रकरण थोपना करना पड़ता है। इस संबंध में जब हाल ही में दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल भोपाल आया तो उसने बताया कि हम मप्र से बिजली खरीदकर 200 युनिट के मात्र सब मिलकर 450 वसूलते हैं। जबकि मप्र में रुपए 1200 का बिल और भांति-भांति के कर लगा रुपए 1400 से लेकर रुपए 3000 से 4000 तक अस्थाई कनेक्शन में वसूले जाते हैं। बेशक इस पाखंडी मुख्यमंत्री शिवराज को जनता को जवाब देना ही चाहिए।

विकास की गाथा

हिंदुत्व के परचम तले गालियां और बकवास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
भक्तों वाली मुझमें आस्था, मूर्खों का विश्वास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
आता जाता कुछ नहीं, बोलता पर बिंदास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
बैन लेकिन निर्यात में अव्वल मैं गौ माता का मांस हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
खोखली शान बघारने को बदला गया इतिहास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
राम मंदिर के झांसों में फिर चुनाव जीतने का प्रयास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
हूँ फ़कीर, वस्त्र, भोजन, भ्रमण का करता भोग विलास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
अंदर से हूँ पूरा चिरकुट, बाहर से बड़ा झकास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बस बना पाया संडास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
डुबा के पूरी अर्थव्यवस्था करता विदेश प्रवास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
खून भले पी लिया देश का, करता पर उपवास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
वोट देने वालों की अक्षम्य भूल का एहसास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
नोटबन्दी में बिफ़रने वालों की पीड़ा का आभास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
बिना ऑक्सीजन मरते बच्चों अकाल त्रास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
बहनों पर डंडे चलवाता, ओढ़े एन्टी रोमियो लिबास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
भूख से जूझते जन की वेदना, पूंजीपतियों का उल्लास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
सीमा पर लड़ते जवानों की शहीदी का अनुप्रास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
शांति, प्रेम, सौहार्द, मानवता सब कर चुका ग्रास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
लोकतंत्र जो पी रहा घूंट घूंट वो विष भरा गिलास हूँ,
हाँ, मैं ही विकास हूँ
तिल तिल कर जो मरने लगी वो अच्छे दिनों की आस हूँ
हाँ, मैं ही विकास हूँ
हाँ, मैं ही विकास हूँ...

इस कविता का किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नही है।

(व्हाट्सएप से प्राप्त)

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण- भ्रष्टों, जालसाजों और मूढ़ो का अड्डा

निकम्मे प्र.स. रजनीश वैश्य को कब हटायेगी सरकार

नर्मदा घाटी में सबसे ज्यादा परियोजनाओं में लेटलतीफी, अव्यावहारिक उदवहन परियोजनाओं की केवल मोटा धन हड़पने भरमार, फिर बैठाये गये सारे मुख्य अभियंता घोर मूढ़ और जालसाज परंतु उपाध्यक्ष ही निकमा और भ्रष्ट

मप्र की पावन नर्मदा नदी पर बांधों से जल और विद्युत उत्पादन नहरों से सिंचाई के नाम 1980 से बना नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यथार्थ में सभी मुख्यमंत्रियों के लिए निर्माण और पुर्नवास के नाम मोटी लूट, भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई की दुधारू गाय बना हुआ है, इसलिए वहां उपाध्यक्ष, मंत्रियों से लेकर सदस्य अभियांत्रिकीय और वहां से अंतिम इकाई पर बैठे उपयंत्रियों तक घोर भ्रष्ट, जालसाज और मूढ़ों की नियुक्ति की जाती रही है, मप्र के जल संसाधन विभाग से निकाल और चुनकर।

यही कारण है कि इस भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में घोर भ्रष्ट और निकम्में प्र.स. रजनीश वैश्य को 5 वर्ष से ज्यादा समझ से मुख्यमंत्री शिवराज ने मोटी कमाई के चलते नहीं हटाया है, फिर सदस्य अभियांत्रिकीय मालवीय भी यहां बैठकर पुरानी लंबित परियोजना लागू यथा नहरों के निर्माण चाहे वो इंदिरा सागर हो, रानी अवंतिकाबाई सागर की दांयी-बाई नहरें, ओंकारेश्वर की दांई-बांई नहरों उनकी लघु नहरों और वितरणियों के निर्माण कार्यों को वो पूरा करवा ही नहीं पा रहे हैं। जिनमें 17 समय विस्तार स्वीकृत कर आंख भींचकर मोटा कमीशन हजम दोगुनी से चार गुनी लागत का भुगतान कर ठेकेदारों ब्यानी, कर्णसिंग, मधुकॉन आदि अनेकों इंदिरासागर, रानी अवंतिका बाई ओंकारेश्वर की दांयी-बाई नहरों में किया और करवाया। प्रमुख अभियंताओं, सदस्य अभियांत्रिकीय न केवल घोर भ्रष्ट और जालसाज है, जिन्होंने पिछले 25-30 वर्ष से सेवा काल में अनेकों भ्रष्टाचार किए, जिनकी अनेकों जांचें लंबित है। पर लूटने लुटाने के चलते 99 प्रतिशत भ्रष्टाचार के मामले सामने ही नहीं आए, जो 1 प्रश मामले सामने आए जिन पर प्रशासन ने संज्ञान लिया उन्हें भी दस्तावेजों के ढेर में दबा दिया गया। और सभी भ्रष्टों को पदोन्नतियां दे दी गई। मंडल क्रमांक 8 के अधीक्षण यंत्री ह्दय राम चौहान के मान परियोजना के भ्रष्टाचारों की जांच के परिणाम अभी तक सामने क्यों नहीं लाये गये। सं.क्र. 25-28 में बैठे का यं. मीणा जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करते हुए एक ही स्थान पर वर्षों से क्यों बैठा है। यहां तक कि मार्च और अप्रैल में कई उपयंत्रियों का हड़ताल में मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि उनका वेतन काटा जायेगा। उन्हें पूरा वेतन केवल सहा. यंत्रियों और कार्यपालन यंत्रियों ने पूरा भुगतान क्यों और कैसे कर दिया गया। जिसे अधीक्षण यंत्रियों मुख्य अभियंताओं, सदस्य अभियांत्रिकीय के साथ उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य ने क्यों नहीं संज्ञान में लिया।

यदि नर्मदा घाटी प्राधिकरण में सारे कार्य निर्धारित समय से दुगुने समय पर भी पूरे हो जाते तो वर्तमान में केवल पश्चिमी मप्र के जिलों से जो कृषि उत्पादन होता उससे पूरे प्रदेश का पेट भरा जा सकता था। नर्मदा की नहरों से होने वाली सिंचाई से पर यथार्थ में सत्ताधीशों का मंतव्य इन परियोजनाओं को पूरा कर कृषि भूमि को सींचना नहीं व बैंक खातों अपनी जेबें और देशी विदेशी को सिंचाई करना ज्यादा जरूरी थी। देश की जनता की, किसानों की समृद्धि से उल्टे ही देश की बर्बादी जन-धन की बर्बादी से इन्हें कोई लेना-देना नहीं। मप्र और देश में 1970 के बाद से, बनाई गई सारी उदवहन परियोजनाओं भारी खर्चीली ज्यादा कारगार, सिद्ध न होने के बाद भी इस भ्रष्टाचार प्राधिकरण ने खरगोन, नर्मदा, क्षिप्रा जिसने 10 प्रश समय भी पानी नहीं रहता, न पंप चलाये जाते फिर भी धड़ल्ले से नई परियोजनाएं मोटा कमीशन खाने के लिए लगातार बनाई जा रही है। जबकि इन योजनाओं को बनाने व चलाने वाले मुख्य अभियंता रंजन रोहित जो घोर भ्रष्ट और जालसाज होने के साथ मूढ़ता का भी परिचय देता है। इसका भी जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध है, इसलिए सूचना के अधिकार में जानबूझकर अपना जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र को तृतीय पक्ष कहकर बचता है। इसके ऊपर ही जांचें लंबित होने और से सह पुस्तिका भी गड़बड़ी की गई है। जबकि ये सब धारा 4 में साइट पर सार्वजनिक की जानी चाहिए। मुख्य अभियंता अजनारे जो कि 6 वर्षों से ज्यादा समय से इंदौर में जमे थे, स्वयं स्थानांतरण करवाकर सनावद और रंजन रोहित को इंदौर, पदस्थ करवा दिया। अधीक्षण यंत्री रहते हुए इनके अंतर्गत कार्य की बारिकी से जांच की जानी चाहिए। आखिर नर्मदा घाटी में जब सारे इंजीनियर प्रतिनियुक्ति पर ही आते हैं। तो इन्हें हर तीन साल में मूल जल संसाधन विभाग में इसीलिए नहीं भेजा ताकि ये अपने अनुभव के हुनर से वर्षों तक अपनी जालसाजियों से भ्रष्टाचार कर खुब लूटे और मुख्यमंत्री तक परियोजना के ऊपर तक पहुंचा।

मप्र जलसंसाधन, चारों तरफ लूट का तांडव

मंत्री, प्र.अ. से उपयंत्री तक सब पी रहे भ्रष्टाचार का घी

हर संभाग में हर माह करोड़ों का आवंटन, सूचना अधिकार में जानकारी मांगने पर हर का.यं. कहता है, काम ही नहीं, काहे की जानकारी। नए तालाबों में 40 से 60 प्रश नहरों व पुराने तालाबों, बांधों में रखरखाव का 60 से 80 प्रतिशत तक फर्जी बिलों से हजम। भ्रष्टों और जालसाजों पर कड़ी कार्यवाही हो

मप्र जल संसाधन कार्य विभागों में से सबसे ज्यादा धन आवंटन पाने वाला, सबसे बड़ा विभाग है, जिसमें 150 के लगभग संभाग, 48 के लगभग अधीक्षण यंत्री 15 के आसपास मुख्य अभियंता है। बेशक पूर्व के प्रमुख सचिव रहते विभाग ने 35 लाख है. में सिंचाई व्यवस्था कर मप्र की कृषि को सुधारा, साथ ही महाभ्रष्ट विभाग की छवि को भी बदला, पर उनके हटते ही और प्रमुख अभियंता के रूप में सुकलीकर के बैठाये जाने के बाद पुनः अपनी पारंपरिक छवि और भ्रष्टाचार को श्रेष्ठता प्राप्त करने में जुट गया। वैसे प्रमुख अभियंता के रूप में हर माह आवंटन 2 प्रश, निविदायें लो.नि.वि. की पद्धति पर अब मुख्यालय में ही केन्द्रीकृत हो जाने से निविदायें खोलने में भी 1 से 2 प्रश तक वसूली का खेल मुख्यालय स्तर पर होने से मोटी कमाई की व्यवस्था है। इसलिए ये हरामखोर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर अत्याधिक वृहद जानकारी होने का बहना बनाकर आवेदन और अपील खारिज कर देते है। जैसे ये सरकारी विभाग नहीं, इनकी अपनी जागीर हो, बेशक भ्रष्टाचार इस विभाग में कभी कम नहीं रहा, चाहे प्रमुख सचिव के रूप में रा. श्याम जुनालिया हो या पंकज अग्रवाल, सबने चुपचाप अपना हिस्सा हजम कर भ्रष्टों को संरक्षण देने का सिलसिला अनवरत चल रहा है। खरगोन में पदस्थ अ.यंत्र बागोरा जो पहले खरगोन में ही सहा. यंत्री, खरगोन संभाग में, फिर का.यं. खरगोन सं. में और अब अधीक्षण यंत्री खरगोन मंडल मं ही बिराजकर, पिछले 20 वर्षों में रुपए 150 करोड़ से 200 करोड़ का चूना लगा चुके है, शासन को बड़ा लंबा इतिहास है। इनके हर कदम हर पद पर रहते हुए किये गये जिसमें एक ही कार्य के 3-3, 4-4 बार निविदायें बुलवाकर पुराने पैसे हजम कर फिर से काम शुरू करवाये गये। इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के कृत्य डीपीआर और डिजाइन कुछ, फाउंडेशन कुछ 30 से 40 प्रश हजम कर कार्य कुछ करवाये गये, वर्तमान में ऐसा ही सबकुछ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, संभागों में चल रहा है, जहां हर महीने करोड़ों के आवंटन में से 25 प्रश से 40 प्रश तक की बंदरबांट चल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक ही व्यक्ति अपने सारे भ्रष्टाचारों को आराम से अंजाम देता हुआ कैसे बैठा है। बेशक लूट के माल में से, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता से लेकर प्रधान सचिव और मंत्री को भी नियमित रूप से लूट में से धन लुटाकर, जनधन के अरबों रुपए की बर्बादी और बिल लगाने के बाद सीधा ठेकेदार के खातें में पैसा जाने से से ऑनलाइन भुगतान से बिल लगाने के बाद सीधे ठेकेदार के खातें में पैसा जाने से भ्रष्टाचार नहीं होता, भाई नाम पुस्तिका पर हस्ताक्षर तो उपयंत्री, सहायक यंत्री ही मुफ्त में तो नहीं करेगा, फिर नाप पुस्तिका भरना, बिल बनाना, बिल स्वीकार कर भुगतान के लिए पूर्ण मान भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि तो स्टॉफ की ही करना है तो ठेकेदार को भुगतान के स्तर तक लाने में भी तो भुगतान करना पड़ता है। फिर कार्य तो मैदानी क्षेत्रों में ही होगा। आप सारा कार्य जो कागजों पर होता है उसी का कम्प्यूटराइजेशन कर सकते हैं। इस संबंध में दतुनी बांध व उसके नहरों के कार्य को ही ले, जो कि देवास संभाग में कन्नौद तहसील में 2013 से 2015 के बीच बांध का कार्य उस समय के तत्कालीन प्रधान सचिव जुलानिया के किसी राजस्थानी रिश्तेदार ने ठेके पर लिया था। उस समय के तत्कालीन का.यं. एच.एन. गुप्ता और उसके सहा. यंत्री यवले जिसने एक ही संभाग में रहते हुए 16 वर्ष पूरे कर लिऐ थे, इस रु 185 करोड़ के बांध में करीब रुपए 30 करोड़ की बंदरबांट हुई। जिसमें लगभग 3 से 5 येवले और इतना ही गुप्ता, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता डाबर ने कमाया। बांध के नाम ने तो मोटी कमाई के बाद येवले की और गुप्ता की कहानी खुले इसके पहले उसको पदोन्नत कर अधीक्षण यंत्री और येवले को का.यं. का प्रभार देकर बेतूल भेज दिया गया। जबकि बांध के बाद बनने वाली नहरों की खुदाई में भी रा.रा. क्र. 59 में की कन्नौद के पास क्रॉसिंग पर खड़ी खुदाई सिद्ध करती है कि वर्तमान भ्रष्ट का.यं. मुकेश चतुर्वेदी की कार्यशैली क्या है। नहरों की खुदाई तल पर सकरी और ऊपर कम से कम दोगुनी चौड़ी व्ही आकार से होनी चाहिए। जो सीधी खड़ी कर गई, इसके अतिरिक्त देवास में अनेकों अन्य कार्यों में भी जमकर 20-30 प्रतिशत का कमीशन चतुर्वेदी हजम कर रहा है। नर्मदा तापी कछार में बैठे मु. अभि. डाबर के 16 संभागों को जन. 17 में रुपए 13.40 लाख मिले जिसमें देवास को रुपए 34 लाख, गांधी सागर को रुपए 69 लाख, इंदौर को रुपऐ 49 लाख, फिर जन. 17 में प्लान 41, में रतला को रुपए 2 करोड़ 65 लाख मनावर को रुपए 79 लाख, बड़वानी की 20 तालाबों के लिए रुपए 10 करोड़ 64 लाख, झाबुआ को रुपए 3 करोड़ 46 लाख, अलीराजपुर को रुपए 91 लाख, धार को रुपए 8.50 लाख, खरगोन 41, धार में 3 से रुपए 70 लाख, बड़वानी को 1 करोड़ 13 लाख, 45 प्लान में नीमच को रुपए 2 करोड़ 25 लाख, रतलाम को रुपए 2 करोड़ 79 लाख, देवास को 10 तालाबों के लिए रुपए 7 करोड़ 27 लाख, धार को रुपए 3 करोड़ 34 लाख, 45 आर-3 में खरगोन को रुपए 44 लाख, धार को रुपए 24 लाख, शाजापुर को रुपए 30 लाख खरगोन को रुपए 50 लाख, खंडवा को अगस्त 17 में सुरक्षा रखरखाव के नाम पर रुपए 32 लाख, मध्यम रखरखाव के नाम शाजापुर को रुपए 42.50 लाख, भवन के रखरखाव के नाम पर हर माह में हर संभाग को पूरे मप्र में रुपए 1 से 10 लाख तक पहुंच के आधार परद स्वीकृत होता रहता है, जो पूर्णतः फर्जी बिलों से हजम कर लिया जाता है। छोटे तालाबों और नहरों के रखरखाव के नाम देवास को रुपए 26 लाख, धार को रुपए 45 लाख, खंडवा को रुपए 30 लाख, नीमच को रुपए 68 लाख, रतलाम को रुपए 50 लाख, शाजापुर को रुपए 20 लाख, उज्जैन को रुपए 11 लाख, अलीराजपुर को रुपए 23 लाख, वि.धा. खंड धार को रुपए 30 लाख, मध्यम सिंचाई शाजापुर को रुपए 42 लाख, धार को लघु रखरखाव के लिए रुपए 45 लाख, देवास को रुपए 26 लाख, खंडवा को को रुपए 5.30 लाख, नीमच को रुपए 68 लाख, रतलाम को रुपए 50 लाख, शाजापुर को रुपए 20 लाख, उज्जैन को 11 लाख, बुरहानपुर को रुपए 15 लाख, अलीराजपुर को रुपए 23 लाख प्राप्त हुए। अर्थात ग्वालियर के चंबल कधार, गंगा कधार, बोधी, राजघाट, आदि के विद्युत यांत्रिकीय व रखरखाव खंडों को हर माह किसी न किसी मद में लाखों से रुपए 10 छोटे तक का आवंटन किसी न किसी तरह से प्राप्त होता है। पर जब भी विशेष तौर पर नर्मदा तापी कधार के मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्रीयों से लेकर कार्यपालन यंत्रियों तक सूचना के अधिकार में जानकारी यह जानने के लिए मांगी जाती है कि आखिर जनधन का कहां कितना सदुपयोग किया जा रहा है। हरामखोर भ्रष्टों की फौज के पास एक ही ब्रह्म वाक्य होता है कि नहीं कोई काम ही नहीं है, कैसी जानकारी, जिसमें सबसे धूर्त व जालसाज अधीक्षण यंत्री, खरगोन मंडल बीपी भगोरा जिसके अंतर्गत खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर संभाग आते है। न इस हरामखोर ने स्वयं आदेशों के बाद अपने मंडल की जानकारी और न ही संभागों की जानकारी संभागों को देने दी, रखरखाव 45 आर-3, एकआईबीपी के ही कार्यो की बारिकी से, विश्लेषण और अनुसंधान किया जाए तो भगोरा को हर प्रकरण में 1992 से 2009 तक सहायक यंत्री और का.यं. के कार्यकाल में किए गए जालसाजी पूर्ण कार्यों में 7 वर्ष की सजा मिले तो शायद पूरा जीवन जेल में ही गुजर जायेगा, वैसे तो हर कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंताओं के कार्यो की आपराधिक दृष्टि से समीक्षा की जाये तो जीवन से ज्यादा जेल के पात्र होंगे। प्र.स. जुलानिया, पुनः जल संसाधन बना दिए गए हैं। पर वो भी इस धूर्त भगोरा को खरगोन से हटाने में कामयाब तो दूर उसे वहीं पर अधीक्षण यंत्री बना दिया। वर्तमान में भी नर्मदा तापी कछार में इन चारों संभागों में ही सबसे ज्यादा निर्माण कार्य चल रहे है। भगोरा अपनी उसी कार्यशैली से अपने अधीनस्थों से जालसाजी पूर्ण तरीकों से ही कार्य करवा मोटा हिस्सा डकार रहा है। बेशक जो जितना भ्रष्टाचार करके लूटेगा वो उतनी आसानी से मंत्री संत्री को लूटाकर अपने आपको बचायेगा। फिर डाबर ने अपने ऐसे सारे वसूली कार्यों के लिए अपने पूर्व चहेते एस.के. पंवार को गैर कानूनी तरीके से कानूनी सलाहकार बना रुपए 10 हजार प्रतिमाह पर अलग कक्ष देकर बैठा ही रखा है। जिसके बारे में प्र.स. जुलानिया भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां सेवानिवृत्त बड़ा बाबु जिसने धार में चार माही में भारी भ्रष्टाचार की वसूली मुख्य अभियंता ने उसे पुर्न नियुक्ति देकर कार्यालय में ही बैठा रखा है। अब जुलानिया पुनः जल संसाधन में लौट ही आये है। तो कम से कम घोर भ्रष्टों पर न केवल कानूनी कार्यवाही वरन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए। भ्रष्टाचार कम हो, वित्तीय लक्ष्यों के साथ भौतिक लक्ष्य पूरे हो, और सिंचाई सुविधाओं से कृषि उत्पादन बढ़े और प्रदेश के 60 लाख किसान लाभन्वित हो।

भूतपूर्व स्व. राष्ट्रपति ने कहा था न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुए के अड्डे

न्यायालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, एसआईटी, एनआईए सब सत्ताधीशों के रखैल

सत्ताधीश ही अंधों की तरह पदों की रेवड़ी सभी विभागों में चीन्ह-चीन्ह कर उन्हीं को देते हैं, जिसका भूत, वर्तमान उनके हितों से जुड़ा हो और भविष्य में भी उनकी इच्छा का पालन करें

धरती पर जन्मा हर मानव, चाहे फिर वो साक्षात विष्णु के अवतार रामकृष्ण ही क्यों न हो, साधारण मानवीय दोषों, काम क्रोध, मद, मोह, माया, यश के पाश में बंधा हुआ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन चक्र को पूरा करता है। चाहे फिर वह सर्वोच्च, उच्च व अन्य न्यायालयों का न्यायाधीश, जांच एजेंसियों का संचालक जिसमें भारतीय जांच एजेंसियां में रॉ, सीबीआई, एनआईटी, एसटीएफ, राज्यों के लोकायुक्त, प्रधानमंत्री, से लेकर चुने हुए सरंपच, पंच, पार्षद, या सरकारी नौकरी के बाबू, चपरासी से लेकर देश के असली भा. प्रताड़ना सेवा बनाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, सब घोर भ्रष्ट, अय्याश, मक्कार, जालसाज होते हैं। बेशक ये जन्म से नहीं वरन परिस्थितियों और मानवीय दोषों के कारण इस देश के कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों के चलते हुए प्रणाली में ढलना इनकी मजबूरी बन जाती है। अन्यथा सत्यवादी और ईमानदार बनने के कारण वो किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने की क्षमता ही नहीं रखते है। अधिकांश शासकीय पदों पर बैठे अधिकारियों का ईमानदार होना, ईमानदारी से कार्य करना, उनका अभिषाप बन जाता है। फिर ये केवल भारत में ही नहीं वरन धरती पर बसी अधिकांश सभ्यताओं और देशों का यथार्थ है। फिर राजनीति और वह भी लोकतांत्रिक राजनीति जिसमें लूट से लूट का, लूट के लिए ही के दम पर, राष्ट्र के श्रेष्ठतम पदों पर पहुंचते हों, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उस नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री से, कि वह जनता से, जनता का, जनता के लिए है, फिर प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, महापौर, सरपंच, पंच, पार्षद, विधायक और सांसद बना है। अब ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च, उच्च न्यायालय के, सीबीआई, एसआईटी, एनआई, के उच्च पदों पर बैठाये जायेंगे इन्हीं प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की मर्जी और अनुशंसा से बिना किसी अतिरिक्त, योग्यता और परीक्षा के, तो स्वाभाविक है कि वो बेचारे अपने आका के विरुद्ध कोई फैसला देने की तो दूर वरन उल्टे ही उनके विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचारों में भी कानून की पदोन्नतियों और प्रकरण की मोटी फाइलों में से सबककुछ नजरअंदाज करते हुए उन्हें स्वच्छ भारत का स्वच्छ नागरिक ही घोषित करेंगें। अब सीबीआई को ही ले, जब कांग्रेस की सत्ता थी तब उसे विपक्षी, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंवेस्टीगेशन कहते थे और जब भाजपा की सत्ता है तो उसे भाजपा इन्वेस्टीगेशन कहते है। जो बिलकुल अक्षरशः अपने नाम की सत्यता को सिद्ध करते हुए, सत्ताधीशों को सत्ता की काजल कोठरी से दूध की सफेदी के साथ निकाल कर लाते हैं। प्रकरण सीबीआई को सौंपे ही इसलिए जाते हैं कि वो सत्ताधीशों को भ्रष्टाचार में घोर काले होने के बाद भी येन-केन प्रकारेण डिटर्जेंट से बने दूध की तरह सफेद सिद्ध करें। इसके विपरीत जो सत्ताधीशों के विरुद्ध जाये तो महाअपराधी सिद्ध करें। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीबीआई, लोकायुक्त, एसटीएस, एनआईए में कौन है, जो ऐसी विशेष जांचों को संपन्न करते है। ये सब कोई देवपुरुष नहीं होते। ये सब भी वही पुलिस विभाग के भ्रष्ट पुलिस वाले ही होते हैं। जो अपने मूल विभाग में ज्यादा भ्रष्टाचार और जांचों को ठंडा करने के साथ इसकी आड़ में मोटी कमाई की व्यवस्था करते रहते हैं। सत्र व जिला न्यायालयों में तो न्यायाधीशों परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार के बाद बनाये जाते हैं। पर उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सबसे बड़ी योग्यता सत्ताधीशों और पूंजीपतियों से संबंध होना ही होती है। ताकि वे सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के हर तरह के प्रकरण में दूध की सफेदी के साथ बचाकर बाहर ले आयें। यही हाल सीबीआई, लोकायुक्तों की नियुक्ति में भी होता है। यदि सचमुच ही ये कानून और जनता के प्रति ईमानदार है तो सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर बहानों की फेहरिस्त क्यों देते हैं। साथ सूचना अधिकार की धारा 4 के 17 बिंदुओं की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालयों,सीबीआई, लोकायुक्त को स्वयं डालनी चाहिए थी। कानून के लागू होने के 12वी बाद भी क्यों नहीं अपलोड की जाती।

साप्ताहिक समय माया

सभी शास. कर्मचारी अधिकारी जालसाज

चुनाव पूर्णतः जालसाजीपूर्ण प्रक्रिया

कदम-कदम पर छलकपट, जालसाजियां कर सत्ताधीशों के इशारे पर नाचा प्रशासन

16वीं लोकसभा के 26वीं सीट का प्रत्याशी बनने के बाद ही यथार्थ में समझ आया चुनाव आयोग और उसके प्रादेशिक और स्थानीय अधिकारियों की चुनावी जालसाजियां जो हर कदम-कदम पर की जाती रही और सत्ताधीश पार्टी के इशारे पर उनके पक्ष में नाचता रहा प्रशासन, सत्ताधीश दल की हर जालसाजी और चुनावी संहिता के उल्लंघन के आंख भींचकर देखता रहा। प्रशासन तो कदम-कदम झूठ और सारी गैर कानूनी गतिविधियां का सह देती रही और गैर भाजपाई व निर्दलीय प्रत्याशियों को कदम-कदम तो चुनाव आयोग के नियमों में ही उलझाए रखा गया, वैसे भी भाजपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार तो महीनों से धुआंधार तरीके से ही चल रहा था। इन्हें तो बस प्रत्याशियों की घोषणा भर करना था, जबकि दूसरी ओर अन्य दलों व निर्दलियों की मात्र 12-13 दिन ही मिले थे, चुनाव चिन्ह आवंटन के पश्चात मिले 12-13 दिनों में वह प्रत्याशी हिसाब किताब रखने और उसके बिलों को इकट्ठा करने में ही उलझा दिया गया, जबकि दोनों दल जो राष्ट्रीय स्तर पर जाने-माने समझे जाते है।

उम्मीदवारी का फार्मा भरने से पहले ही सभाओं और बैनरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके थे, चुनाव आयोग और उसके स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि स्थानीय जिलाधीश संभागायुक्त सबकुछ देखकर भी चुप रहे। चुनावी आयोग केवल ऐसी शासकीय संस्था है, जो दिखावे और जालसाजियां पूर्ण खेल करती है। जिसे 94 प्रश लोग समझ ही नहीं पाते, फिर कमजोर कड़ी कौन, जिसे दबाकर सारे नियम-कानून थोंपकर कार्यवाही करने की नौटंकी की जाती है। कि रुपए 70 लाख की सीमा है। संसद का चुनाव लड़ने की वहा सत्ताधीश दल के व बड़ी पार्टी के लोग 70 करोड़ खर्च करके भी चुनाव आयोग के डंडे से बचे रहत हैं। वहीं दूसरी और छोटे दल, निर्दलीय प्रत्याशियों को उम्मीदवारी के फार्म जमा करने से लेकर, प्रचार-प्रसार के खर्चों, मतदान के दिन से लेकर गिनती वाले दिन तक के हिसाब किताब के खर्चों तक हर कदम उलझने पैदा की जाती है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों, पुलिस व प्रचार माध्यमों के द्वारा, उन्हें प्रताड़ित करना, नीचा दिखाने, मनोबल तोड़ने की कोशिश, उनके फोन टेपिंग, उनके सहयोगियों की फोन टेपिंग, उनके नंबर पर सत्ताधीश प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी से धमकाने, चमकाने, सहयोग न करने की हिदायत दी जाती है। ये सारे कांड मीडिया के भांड और भड़वे जानबूझकर भी जानने के बाद सामने नहीं आने देते, क्योंकि सभी समाचार पत्रों को हर दिन लाखों रुपए के विज्ञापन बांटे जाते हैं। इसलिए वो बड़ी पार्टियों और उनके पदाधिकारियों के उम्मीदवारों की प्रशंसा और आलोचना श्वानों से मिले टुकड़ों के हिसाब से ही करते हैं। इसलिए

ये मीडिया के शूकरों की फौज भी बड़ी राजनैतिक दलों के सारे चुनाव आयोग के नियम कानूनों के उल्लंघन के बाद भी कभी सच नहीं छापते जबकि दूसरी ओर छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के हर छोटे से छोटे कृत्य पर पुलिस प्रशासन और मीडिया वाले भुखरे श्वानों की तरह उन्हें सूंघते फिरते हैं। वैसे भी सत्ताधीश प्रशासन और मुख्यमंत्री चुनाव के पहले ऐसे अधिकारियों को जिलाधीश बनाती हैं, जो घोर-भ्रष्ट जालसाज और उनका वफादार हो इसी श्रेणी में तात्कालीन जिलाधीश त्रिपाठी सांसद सुमित्रा महाजन की वफादारी निभा रहे थे। आम उम्मीदवार के लिए किसी भी सार्वजनिक धर्मस्थलों का चुनावी सभा में उपयोग करने पर मनाही थी, जबकि भाजपा की सांसद उम्मीदवार ने खुलकर 800 सभायें की जिसमें हर सभा पर रुपए 10 लाख भी खर्च किये और अधिकांश सभी हिन्दू समाज के हिन्दू जैन मंदिरों के प्रांगणों, सार्वजनिक निगम के बगीचों और स्थलों पर की गई, पर कोई भी कुछ बोलने की तो दूर उल्टे ही प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा भी प्रदान की। अधिकांश सभाओं की अनुमति भी नहीं ली जाती थी।

चुनाव के लिए मतदान के दिन 2200 स्थानों को मतदान केन्द्र बनाये गये थे। हर मतदान केन्द्र पर न्यूनतम 10 कार्यकर्ताओं को रुपए 1-1 हजार का भुगतान किया गया तो भी रुपए 22 करोड़ खर्च हुए, हर मतदान केन्द्र पर 100 पैकेट नाश्ते के, भोजन के पैकेट पहुंचाये गये, 2200×100×5 रुपए 11 लाख और भोजन का पैकेट रुपए 1 करोड़ 10 लाख के। जबकि चाय और पानी के पाउचों का कोई हिसाब ही नहीं। यही हाल गिनती वाले दिन भी हुआ। 8 विधानसभाओं के 120 केन्द्रों पर 2-2 व्यक्ति बैठाये गये अर्थात 240 व्यक्तियों को रुपए 1000 प्रति व्यक्ति से रुपए 24 लाख बांटे गये। भोजन चाय नाश्ता भी भाजपा ने ही करवाया। जिसमें हर टेबल पर 10-10 चाय, 10 पैकेट नाश्ते और भोजन के भेजे गये रुपए 10 लाख। जबकि रैलियां, पोस्टर, बैनर, बाजे वालों, स्पीकर, मंच की भीड़ और रुपए 500 प्रतिदिन प्रति कार्यकर्ता के हिसाब से मात्र 20 दिन में ही रुपए 200 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए पर हिस्सा व रुपए 70 लाख ही दिया गया। जिसे आसानी से बिना सूंघे मान लिया गया। जबकि निर्दलीयों को हर बात के लिए परेशान किया गया।

दूसरी ओर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन तो पूरी जालसाजी है, ही जब उसकी जालसाजियां सिद्ध करने के लिए कम्प्यूटर विशेषज्ञ बाहर आने को तैयार हुए तो उन्हें डरा धमकाकर चुप कर दिया गया। फिर मतगणना वाले दिन की जालसाजियां देखिये, मतगणना मशीनें खोलने से पहले कहा गया था हर मशीन से निकले कुल वोटों का प्रिंट आउट दिया जायेगा, हर ईवीएम प्रिंटर से जुड़ी है। हर राउंड की, हर मशीन की गिनती की ऑफिस एक्सेल बनेगी वह भी दी जायेगी, फिर 8 विधानसभाओं की हर मशीन की गिनती की ऑफिस एक्सेल की सीट की गिनती की भी कुल गणना की ऑफिस एक्सेल सीट भी दी जायेगी, जबकि ऐसा वहां कुछ भी नहीं किया गया। सबकुछ पूर्ण जालसाजी थी, मशीनें खोलने के साथ ही स्वयं जो हर टेबिल पर 3-3 प्रशासनिक लोगों की टीम बैठी उसमें से एक मशीन लाने, साफ-सफाई कर दिखाने, मतपेटी में जालसाजी नहीं हुई है। सील दिखाने के बाद फिर उसमें हर नंबर के प्रत्याशी को किस को कितने वोट बताने के साथ ही दूसरा सदस्य उसको वितरित 5 शीट पर लिख रहा था। तीसरा सदस्य एक सीट पर उसे लिखने और दूसरी बार पुनः मतो को सत्यापित कर रहा था। मशीन खोलने वाला दिखाने के बाद उसे पुनः बंद करने की प्रक्रिया पूरी कर दूसरी मशीन को लॉकर में लेने जाता था।

हर विधानसभा में लगी 15 टेबिलों पर इस 25 से 35 मिनट की नौटंकी के बाद सीट इकट्ठी करके पूरी विधानसभा की 15 टेबिलों की पहले राउंड की सीट को ऑफिस एक्सेल सीट बनाने के लिए बैठे कम्प्यूटर ऑपरेटर को दी गई। अब कम्प्यूटर ऑपरेटर ने ऑफिस एक्सेल सीट में 15×23 प्रत्याशियों की ऑफिस एक्सेल सीट में 345 प्रविष्टियां करने के लिए प्रति प्रविष्टि 10 सेकंड लिए अर्थात 3450 सेकंड अर्थात 57.5 मिनट या पूर्णतः 1 घंटा। बाद में 8 विधानसभाओं की ऑफिस एक्सेल बनाने में 23×8 बराबर 1840 सेकंड अर्थात आधा घंटा 1 अर्थात 1 राउंड की काउंटिंग में 30+60+30 बराबर 120 मिनट या 2 घंटे लगते हैं। तो 24 चक्र की गिनती और परिणाम घोषित करने में बिना रूके 48 घंटे लगने चाहिए। परंतु किसी भी स्तर पर ऑफिस एक्सेल सीट ही बिना बताये और बताये साढ़े तीन बजे अपनी मनगढ़त सीटे जो अलग कमरों में सहायक जिलाधीशों बनाते रहे। श्रीमती सुमित्रा महाजन को साढ़े चार लाख वोटों से जीतना दिखा दिया जबकि मशीनें शाम को 6 बजे तक खोली जाती रही अर्थात पूरा खेल ही जालसाजी का था। गिनती, वोटिंग, मशीनों से बड़ी जालसाजी है। इस प्रकार चुनाव जीतते हैं। सत्ताधीश उसकी बानगी है। मैंने उम्मीदवार होने के नाते हर मशीन की गणना पत्रक तत्काल और सूचना के अधिकार में भी मांगा जो आज तक नहीं दिया गया। जिलाधीश आकाश त्रिपाठी की इस जालसाजी से खुश होकर इंदौर में ही विद्युत कंपनी का प्रबंध संचालक बना मोटी लूट पाट करने बैठा दिया गया।

मप्र परिवहन विभाग हर कदम जालसाजियों और भ्रष्टाचार

मोटे कमीशन के लिए पूरा परिवहन विभाग निजी ठेके की तैयारी

पीयूसी प्रमाणन वाहन विक्रेताओं को पंजीयन देकर मोटे कमीशन और कानून की धज्जियां उड़ाने से दिल नहीं भरा, विभाग को बंद कर सभी कार्य अलग-अलग ठेके पर देने की तैयारी कानून बाप की जागीर मान की जा रही है।

पूरे भारत के परिवहन मंत्रालय में केन्द्र से लेकर हर राज्य के मु.मं. परिवहन मंत्री से लेकर प्रधान सचिव,सचिव, आयुक्त, क्षेत्रीय व जिला परिवहन, अधिकारियों से लेकर बाबु, चपरासी और जालसाज दल्लों, ऐजेन्टों के गिरोह ने पूरे परिवहन विभाग को लूट, डकैती के साथ ही जालसाजियां और फर्जीवाड़ें का अड्डा बना दिया है। बेशक यहां निरीक्षकों के बाबुओं की कार्य की आवश्यकता के अनुसार घोर कमी तो जानबूझकर बनाकर रखी गई है। साथ ही महत्वपूर्ण कार्यों जैसे वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण, मैकेनिकल, इंजीनियरों की भर्ती होना चाहिये, वहां प्रारंभ से ही गैर तकनीकी व्यक्तियों को बिना तकनीकी प्रशिक्षण की परंपरा गत सामान्य परीक्षाओं से भर्ती की जा रही है। वाहनों की फिटनेस में और प्रदूषण जांच में बिना, मेकेनिकल इंजीनियर आईटीआई और 8वीं, 10वी पास लोगों को मोटा कमीशन लेकर जांच प्रमाण पत्र देना कहां तक न्यायोचित है। पर सब कुछ मोटी वसूली कर धड़ल्ले से वर्षों से चल रहा है। अब जबकि पंजीयन का कार्य भी वाहन विक्रेताओं को सौंपकर हर वाहन पर रुपए 1000 ज्यादा की वसूली उल्टे सीधे आधारों पर की जा रही है। पूरे देश के परिवहन विभाग में निरीक्षकों और बाबुओं व अन्य स्टॉफ के कार्यभार को देखते हुए संख्या 60 से 40 प्रतिशत ही है। हर बाबु, निरीक्षक व अन्य कर्मचारियों ने स्वयं के कार्यभार को हल्का करने, समय सीमा में कार्य पूरा करने के बदले में प्राप्त अवैध धनराशि बटोरने स्वयं की वसूली में वैतानिक अवैध रूप से कर्मचारियों को बैठा रखा है। जिसे अनेकों बार समाचार पत्रों में छापा जा चुका है। सभी बड़े अधिकारियों से लेकर परिवहन आयुक्त, सचिव, प्रधान सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी इसकी जानकारी है, परंतु अवैध अरबों रुपए प्रतिमाह की वसूली के चलते सबजानकर भी चुप इसलिए ही बैठे हैं। कि स्थायीं कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के बाद उनका भी हिस्सा बांटना पड़ेगा। साथ ही सारा मामला बाहर भी फैलेगा, फिर 2014-15 में परिवहन आरक्षकों की भर्तीयां की गई थी जिसमें 150 आरक्षक गोंदिया के चयन कर लिये गये थे। जिस पर व्यापमं में भारी विवाद हुआ था, अंत में सारी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी।

भाजपा अर्थात मुखेरा जन पार्टी अपनी लूट वसूली और मोटे कमीशन के लिए देश की सुरक्षा को बलाये ताक रखकर जिस तरह से अधिकांश विभागों को बंदकर निजीकरण की तरफ धकेल रही है। उससे तो इनकी राष्ट्रभक्ति कोरो पाखंड सिद्ध हो रही है। यदि परिहवन विभाग में पंजीयन फिटनेस, अंतरण, परमिट, प्रदूषण नियंत्रण आदि सभी निजी हाथों में चला गया तो का हे की राष्ट्र की, जनता की, जलवायु की सुरक्षा और नियमन, अभी आधी जालसाजी, दुगुना भ्रष्टाचार होता है, फिर निजी क्षेत्र में जाने पर बिजली की तरह दुगुनी जालसाजियों, चौगुना से 40 गुना तक भ्रष्टाचार, परमिट, फिटनेस, प्रदूषण अनियंत्रित, किसी की कोई सुरक्षा नहीं, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के विदेशी पते पर भारत के लायसेंस बनेंगे, अभी कम से कम औपचारिकतायें पूरी होती है फिर निजी हाथों में जाने पर सरकारी गाड़ियों में भी आतंकी शान से घूमकर लोकसभा, विधानसभाओं में भी आसानी से घुसेंगे, सारे परमिट निजी कंपनी के ही लोगों के पास होंगे, फिटनेस के नाम सारे काम आंख भींच पैसे लेकर घर बैठे ही पहुंचा दिये जायेंगे, बेशक परिवहन विभाग के निजीकरण को बंद कर निजी क्षेत्र में देने की सलाह मुख्यमंत्री को दी थी जिसे मोटी कमाई देखकर निजी क्षेत्र में हर कार्य को अंतरण करने की तैयारी कर ली गई। अभी जो खेलरुपए 2000 करोड़ प्रतिमाह पूरे मप्र में है, जिसमें बाबु, चपरासी, एजेंटों का भी हिस्सा होता है, मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, सचिव,आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन,जिला परिवहन अधिकारी, निरीक्षकों आदि सबको बंटता है। साथ ही जिलाधीश संभागायुक्त भी परमिट आदि को मोटे हिस्सा भरते है। इसीलिये ही पूरे देश में सभी राज्यों की परिवहन निगमों की बसें चल रही हैं। पर मप्र में नेताओं अधिकारियों की लूट मोटी लूट के चलते सर्वोच्च न्यायालय और प्रधान मंत्री के निर्देशों के बाद भी परिवहन निगम इस हरामखोर जालसाजों ने परिवहन निगम को शुरू करने कुछ नहीं किया।

दिल्ली की प्रदूषित धुंद से 10 करोड़ की जिंदगी खतरे में, जिम्मेदार कौन?

पेज 1 का शेष

बेशक अरविंद केजरीवाल ने सम-विषम संख्या की कारों को चलने से रोकने के लिए नीति तैयार की थी उसे स्वीकारने को अपेक्षा हमने हमारे राजनीतिज्ञों ने मात्र उसे नीचा दिखाने की नियत मात्र से ठप्प कर दिया। ये वही आपराधिक राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने मोटे कमीशन के लिए बिना इसका ख्याल किए कि जब करोड़ों वाहन बनने के बाद सड़कों पर दौड़ेंगे तो इनसे निकलने वाले धुयें से कितना प्रदूषण होगा उसके देश में उत्पादन करने और बिक्री करने की खुली छूट दी, पर्यावरण की तो दूर सड़कों और खड़ा करने की व्यवस्था तक का ख्याल नहीं रखा गया उल्टा ही बैंकों के दरवाजे खोल सस्तें में ऋण की व्यवस्था कर दी गई। दूसरी तरफ जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन जो पेड़ों द्वारा उत्सर्जित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमने अपने लालच के चलते उन वनों, हरियाली की सफाई करके पहले गांव बसाये, वनों की जमीनों पर कब्जे करवाये, फिर उन गावों को शहरों में बदल दिया फिर उन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने और कलोनियों, बहुमंजिला इमारतों, सीमेंट की सड़कों का कांक्रीट जंगल खड़ा कर दिया। भूमाफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया, कॉलोनी माफिया जो हर बड़ी राजनैतिक पार्टी को मोटा चंदा देते थे अपने कारोबार को बचाने स्वयं ही नेतागिरी करने लगे थे, उन्होंने बड़ी आसानी से धन, बल के दम पर संसद और विधानसभाओं में बैठकर कानूनों को जो जल, जंगल, जमीन, जलवायु, जनों के हितार्थ बनाये गये थे। को ही बदलवा दिया, संशोधन करवा लिए, ताकि वे अपनी मोटी कमाई के लिए मनमर्जी से नदियों, नालों, जंगलों, पहाड़ों, जलबहाव क्षेत्रों, तालाबों, चरनोई भूमि, खेतों, सरकारी भूमि पर कब्जे कर अपनी कालोनियां, फैक्ट्रीयां, उद्योग लगाकर अपनी मोटी कमाई कर सके। सारी सरकारी एजेंसियां यथा वन विभाग, पटवारी से लेकर तहसीलदार, सहायक, उप व जिलाधीश स्तर के राजस्व अधिकारी, नगर निगम, प्रदूषण मंडल, उद्योग विभाग जो घोर भ्रष्ट है। पैसे हजम कर ऐसे सारे भूमाफिया कटाई माफिया, खनन माफियाओं, उद्योगपतियों, कॉलोनी माफियाओं, के इशारे पर नाचकर सारे कुकर्मों पर छापे ठोंकता रहा, पूरे देश में। खासतौर पर राजधानी और उसके चारों तरफ 200 किमी के क्षेत्र में हरियाली साफ होती रही, नदी नाले सिकुड़ते रहे। आधुनिकता के नाम पर कांक्रीट जंगल खड़े होते रहे, जीवन के लिए अतिआवश्यक ओषजन वायु और जल प्रदूषित होते गए। भू-गर्भ, भूतल और नभ का, यह प्रगति नहीं यथार्थ में विनाश का विकास होता रहा, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु के लिए जिम्मेदार बीमारियां बढ़ती गई। जिसको जनता ने चुनकर भेजा व सत्ता संभालते ही देवता से लालची दानव बन अपने नश्वर व क्षणिक स्वार्थों के लिए जन, जानवर, जलीय, थल चर, नभचर, जंगल, जमीन, जल, का घोर शोषण में जुट नगदीकरण करने में जुट गया। जागो अभी समय है संभलो इस विकास बनाम विनाश लीला को रोको अन्यथा यह सब इस मानव व अगली शताब्दी समाप्त होने से पूर्व ही समाप्त कर देगा।

जन, जंगल, जमीन को नोंचा खाया प्रदेश कर दिया कंगाल

ऋण ले, घी पिया, किया भ्रष्टाचार का तांडव

पेज 1 का शेष

शिवराज के मुख्यमंत्री रहते सभी विदेश यात्रा जो कि निवेशकों को बुलावा देने के नाम पर की गई थी, यथार्थ में प्रदेश में भ्रष्टाचार और लूटपाट से प्राप्त धन का निवेश करने के लिए की गई यह धन जो कि प्रदेश मं केवल विद्युत को ही देखे तो हमारे प्रदेशे से विद्युत खरीदने वाली देश की राजधानी दिल्ली में 200 युनिट का विद्युत बिल मात्र 450 होता है वहीं बिजली प्रदेश के नागरिकों के घरेलु उपयोग में रुपए 1400 की, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रुपए 2500 से 3000 की, अस्थाई कनेक्शन में रुपए 3 से 4 हजार की बेंची जाती है। दूसरी तरफ मोटा धन कमाने के लिए टाटा पॉवर, रिलायंस पॉवर से, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन विद्युत जिसकी उत्पादन लागत ताप विद्युत में रुपए 1 से 1.25 पैसे, जबकि पूंजीगत और आगाम खर्चो में सौर व पवन ऊर्जा जो कि मात्र रुपए 25 से 40 पैसे होती है रुपए 5.50 में जानबूझकर रुपए 3 से 4 रुपए तक का मोटा कमीशन हजम करोड़ों रुपए रोज की मोटी कमाई की जा रही है। जबकि प्रदेश की जनता के घरों में लगाये गए मीटरों में आधारभूत 50से 500 प्रश तक तेज मीटर लगाकर वसूलने के बाद भी, ताले लगे घरों में शून्य के मीटर वाचन पर भी हरामखोर जालसाज कं. 1000-2000 तक यूनिट तक के बिल ठोकती और कुर्की कर डरा धमकाकर लूट रही है। जैसा कि प्रवीण कुमार जैन, 353 फर्शी वाली गली भागीरथ पुरा इंदौर के बिलों में पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। यही हाल प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के साथ किया जाकर चारों तरफ लूट का तांडव मचा ये गिद्ध जनता से भी अरबों रुपए लूटकर हजम कर रहा है। प्रदेश में 25000 मेवा के उत्पादन होने के बाद भी प्रदेश की जनता अंधेरे में 6 से 18 घंटे तक गुजार रही है। रबी के फसलों के मौसम में किसानों को बिजली तो दूर उनसे जबरन हजारों करोड़ के बिल अवश्य बिजली कं. थोप रही है। पर ये श्वान अपना टुकड़ा मुंह में दबा जनता को परेशान होता देख विदेशों में जमा करने चला जाता है।

प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से अच्छा बताने वाले प्रदेश में न केवल प्रधान मंत्री सड़क योजना की 20000 किमी सड़कें, राज्य के राजमार्गों की 17000 किमी सड़कों की हालत दयनीय बने हुए हैं। वही हाल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों के भी है। जहां 2009 स चुंगी वसूलने के बाद भी सड़कें ढंग की नही है। जिसमें देवास से इंदौर, राऊ की सड़क भी हैं सड़कों के निर्माण, मरम्मत में मोटी वसूली के लिए मु.मं. शिवराज ने आजमगढ़िया सुलेमान को पुनः प्रधान सचिव लो.नि.वि. बना दिया। सड़कों के साथ ही पुलियाओं, पुलों कें निर्माण, भवन निर्माण में बनी ईकाई में भी चुन-चुन कर प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट धूर्तों जिसमें इंदौर उज्जैन संभाग के 13 जिलों के, देवास और शाजापुर भोपाल अतिरिक्त परि. संचालक के अंतर्गत है। 13 जिलों के सारे कार्यपालन यंत्रियों से लेकर अति. परि. संचालक खरात तक सब घोर निकम्मे, मूढ़ और भ्रष्ट होने के बाद भी सारे भवन निर्माण जैसे संवेदनशील कार्यों को संपन्न करने बैठा दिए गए।

मप्र में शिक्षा स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों, माफियाओं के चंगुल में फंसी है, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में साधनों और शिक्षकों के अभाव में यथार्थ शिक्षा की स्थिति भी भारी दयनीय कर दी गई है। व्यापमं घोटाले को भले ही धन और सत्ताबल से ठंडा करवा दिया गया हो, परंतु 250 की मौत, 700 से ज्यादा की चिकित्सा महाविद्यालयों से निकाले जाने, निजी स्कूलों और कॉलेजों से मोटा कमीशन हजमकर सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में जानबूझकर परिणाम बिगाड़ना, शिक्षकों को दूसरे सरकारी कार्यों में उलझाकर पढ़ाई बर्बाद करना, परिणाम महीनों वर्षों तक घोषित न कर, निजी चिकित्सा अभियांत्रिकीय, प्रबंधन से लेकर साधारण कला, वाणिज्य विज्ञान से लेकर प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों तक की शिक्षा को निजी शिक्षा माफियाओं की कठपुतली बना मान्यताओं के नाम व अन्य स्त्रोतों से मोटा कमीशन ऐंठा जा रहा है।

पिछले 12 वर्षों में 56 प्रकार के वृक्षों की कटाई की खुली छूट देकर वनों और निजी क्षेत्रों के लगभग 50 करोड़ वृक्ष हर वर्ष पूरे मप्र में कटवाये जाते रहे। साफ हुई वन भूमियों पर कृषि कार्य, वन ग्रामों से लेकर भूमाफियाओं ने कॉलोनी काटने से लेकर फैक्ट्रीयां, रिसार्ट, होटलें, खड़ी करवाने में जहां भाजपा नेता सबसे आगे रहे तो दूसरी तरफ वनकर्मियों को दोनों तरफ उलझाकर रखा गया। सूचित करता है तो विभागीय कार्य वाही के साथ भूमाफिया, खनन माफिया सबसे विवाद के साथ ही कब्जेधारी के पट्टे की व्यवस्था नहीं करता है तो भी विभागीय कार्यवाही के साथ वनकर्मियों को देख या पूछने पर भी विवाद, दूसरी तरफ 2 जुलाई 17 को को 6 करोड़ वृक्ष लगवाने की नौटंकी के नाम अरबों रुपए के विज्ञापन बांटे गये एक तरफ न तो वन और उद्यानिकी विभाग की प्रदेश की रोपणीयों में पौधे न ही दूसरे राज्यों से पौधे मिले, फिर भी 4 से 5 करोड़ पौधों के रोपण में भी लगभग प्रत्यक्ष रूप से रुपए 600 करोड़ पौधे बनाने में और रोपणी कार्य में भी लगगभ रुपए 1200 करोड़ से ज्यादा खर्च कर जनता के जेब पर ही भार डाला गया। जबकि 12 वर्षों में काटे गये 600 करोड़ वृक्षों में रुपए 2 हजार प्रति वृक्ष की कमाई की गई तो भी रुपए 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपए के साथ, वनोपणन, खनन भू अतिक्रमण की कमाई अलग।

स्वास्थ्य विभाग ने रुपए 20000 करोड़ की खरीदी में रुपए 1000 करोड़ की बंदरबांट होती है। सरकारी अस्पतालों से निजी अस्पतालों में भेजने में भी मोटे कमीशन का खेल चल रहा है। सरकार की तो मंशा है, कि मोटा कमीशन दो और सारे सरकारी चिकित्सालय निजी गिद्धों को किराये पर देकर लुटवाओ।

सबसे ज्यादा लूट शहरीय विकास के नाम प्रदेशभर में चल रही है। जहां पहले सीमेंट की सड़कें 25 से 50 प्रश कमीशन पर बिना जल निकासी की व्यवस्था किए और गैस व बिजली के लिए उचित व्यवस्था किए पूरे प्रदेश में हर वर्ष हर जिले में रुपए 10 से 15 हजार करोड़ खर्च करके बनाई गई थी उस पर बाद में नालियों के लिए पूरे प्रदेश के हर नगरीय क्षेत्रों को खोदकर पुनः निर्माण करवाने में हजम किया गया। मुख्यमंत्री, विधायकों से लेकर हर मोहल्ले पार्षदों ने, नगरीय क्षेत्रों में सफाई, जल वितरण व निकासी विद्युत व्यवस्था, निर्माण, सड़कें, शिक्षा स्वास्थ्य, सड़कों आदि पर प्रतिवर्ष रुपए एक लाख करोड़ में सीधे मंत्री व मुख्यमंत्री ने रुपए 10000 करोड़ से ज्यादा हजम किया। यही कारण है कि 90 प्रतिशत नगर निगम व पालिकायें, परिषद सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर भारी नौटंकी और परेशान करने के बाद भी पूरी जानकारी नहीं देते।

ग्रामीण विकास में तो मात्र शौचालय, कांक्रीट सड़कों, मनरेगा, इंदिरा मुख्यमंत्री आवास, नल जल योजन और मध्याह्न भोजन के नाम पर जिसका अधिकांश पैसा केन्द्र से आता है। जो कि रुपए 30 से 40,000 करोड़ होता है। 30 से 40 प्रतिशत केवल भ्रष्टाचार में जाता है। जिसमें से भी मु.मं. प्रधान सचिव, संचालक से लेकर जिलाधीश, मु.का. अधिकारी जिला व जनपद पंचायत सरपंचों तक हजम हो जाता है। शौचालय के नाम पर तो एक ही हितग्राही के नाम 2001-02 से लेकर 17-18 तक हर वर्ष शौचालय बन रहे है। ये भारी भ्रष्टाचार जानबूझकर वोट बैंक की खातिर किया और करवाया जा रहा है। यहां पर 80 से ज्यादा योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए आने वाले पैसे में से 50 से ज्यादा योजनायें केवल कागजों पर ही चलाई जाकर धन हजम किया जा रहा है। मु.मं. चौहान ने बेशक प्र.स. जुलानिया को ग्रामीण विकास की कमान सुधारने को जनपदों के अध्यक्षों से लेकर पंचायतों के सचिव सरपंचों तक को ईमानदारी से कार्य करना सिखा दिया था। परंतु भ्रष्टों को यह हजम नहीं हुआ, उनकी तेज तर्रार कार्यशैली से चिढ़कर ढेरों शिकायतें की गई, फिर भ्रष्टाचार के अभाव में वोट बैंक खिसकता और भ्रष्टाचार से होने वाली कमाई का खेल बिगड़ते मुख्यमंत्री ने वहां वर्तमान और पूर्व मु.मं. के चहेते युगों से भ्रष्टाचार शिरोमणी घोर धूर्त इकबाल सिंग बैस को बैठा दिया ताकि आवंटित धन का 10 प्रतिशत तो मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचे।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति में तो छात्रवृत्ति के नाम और दम पर ही 90 प्रश निजी शिक्षण संस्थायें माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पिछले 30 से ज्यादा वर्षों से फर्जी नामों और कामों के दम पर प्रदेश के 15 से ज्यादा आदिवासी जिलों में विभिन्न योजनाओं में आने वाला रुपए 80 से 90000 करोड़, जो शिक्षा, आदिवासी छात्रावासों, विकास खंडों, में 90 से ज्यादा योजनाओं, निर्माण कार्यों में आवंटित होता है। वर्तमान में भी बड़े-बड़े आपूर्ति, निर्माण आदि के ठेकों के माध्यम से हजम किया जाता है। यही कारण है कि इन आदिवासी जिलों में अधिकांश हरामखोर भ्रष्ट जिलाधीश, जिला पंचायत, मु.कां.अ., सहायक आयुक्त न केवल जालसाज सूचना अधिकार के पत्रों का जवाब नहीं देते वरन शूकरों की फौज अपीलें भी पी जाती है या अपने अधीनस्थों को अपील सुनने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है जैसा कि पिछले कई वर्षों से धार जिलें में बैठे धूर्त जिलाधीश कर रहे हैं।

यही सब हाल गृह, जेल, महिला, बाल विकास, राजस्व, उद्यानिकी, रेशम, उद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, कृषि, वाणिज्य कर, नगर एवं ग्राम निवेश, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, खनन, सहकारिता, परिवहन, श्रम, नर्मदा घाटी, पशुपालन, पर्यावरण आदि हर विभागों में लूट का तांडव और भ्रष्टाचार मचा हुआ हैं। स्वाभाविक है इन सबका हिस्सा मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। इसलिए सूचना के अधिकार की धारा 4 का पालन 12 वर्ष बाद भी नहीं किया जा रहा जिसके आवंटन और उपयोग की जानकारी से लेकर कौन सा कर्मचारी क्या कार्य कर रहा है उसका वेतन व संपत्ति कितनी है। तक को पूरी जानकारी अभी तक साइटों पर न तो डाली जा रही है और न ही आवेदन पर जवाब दिये जाते हैं। ताकि भ्रष्टाचार से धन लूटने में व्यवधान पैदा न हो, जानकारियां का भी खुलासा न हो, अपनी तीस मार खां बनने के विज्ञापनों का सच सामने न आये और ये गिद्ध सत्ता पर कुंडली मार अजगर की भांति प्रदेश की जनता के हितों की आड़ में मोटा धन निगलता रहे। अकेले सिंहस्थ 2016 में खर्च किए गए रुपए 20000 करोड़ में से रुपए 10000 करोड़ का सीधा सौदा हुआ। जिसमें पूरे विश्वभर में विज्ञापनों में ही रुपए 5000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। उस भ्रष्टाचार पर विपक्ष को विधानसभा में बोलने का ही मौका नहीं दिया गया। जबकि जनधन से साधुओं का मुंह बंद करने रुपए 5 से 10 करोड़ तक के लिफाफे दिए गए। वर्तमान हालात ये है। पूरे प्रदेश में हर विभाग में हर कदम भ्रष्टों का बोलबाला है। सरकार चलाने के लिए कर्ज पर कर्ज लेकर घी पी रहे है। मुख्यमंत्री और जनता से पानी बिजली पेट्रोल डीजल पर करो को लाद लूटा जा रहा है।

पूंजीपतियों के इशारे पर ढीठ मोदी ने तबाही मचाई देश में

पेज 1 का शेष

इसी के साथ ही जीएसटी में इनपुट क्रेडिट का भुगतान न होने से निर्यातकों को धनाभाव में उत्पादन बंद करना पड़ गया और निर्यात भी तेजी से घटा। इससे आयातों के भुगतान का बोझ बढ़ गया। अब समस्या यह है कि इनपुट क्रेडिट लौटाई नहीं जा सकती करों से आय के घटने से राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई भी केन्द्र सरकार नहीं कर पा रही है। चारों तरफ से भुगतान संकट से सरकार कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं कर पायेगी, तो दूसरे कल्याणकारी और विस्तार और शहरीय संरचनाओं के लिए भी धनाभाव से रूक जायेंगी, वह तो पेट्रोल डीजल की कमाई और 80 प्रतिशत करों से केन्द्र व राज्य सरकारों के खर्चे चल रहे हैं।

धूर्त मोदी ने एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, सड़कों आदि का बजट कम कर दिया दूसरी तरफ पूंजीपतियों का सन् 2014-15 में रुपए 49018 करोड़, सन् 15-16 में रुपए 49015 करोड़ और सन् 16-17 में रुपए 15163 करोड़ माफ किए, यह ब्यान वित्त राज्य केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने राज्य सभा में दिया था। इसके विपरीत बैंकों का जो ऋण अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जेपी एसोसिएट्स जैसे सैकड़ों का डूबत खाते में पड़ा है।

उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा और बैंकों ने स्वीकार किया कि कार्पोरेट सेक्टर में बैंक धन का 25 प्रतिशत गैर उत्पादक आस्तियों में डूब है। जिस पर सरकार भी कोई कार्यवाही नही कर रही। दूसरी तरफ बैंकों ने अपने इन घाटों को पूरा करने के लिए सभी कार्यों पर यहां तक कि पैसे जमा करने, निकालने पर भी शुल्क थोप जनता को चारो तरफ लूटा जा रहा है। यहां तक सेवा शुल्क के नाम इस गिद्ध ने गरीबों के जो खाते खुलवाये थे न्यूनतम शुल्क की और शेष की आड़ में ही लगभग रुपए 5000 करोड़ से ज्यादा हजमकर खाते ही गायब कर दिए। अकेले स्टेट बैंक ने स्वीकार किया कि रुपए 390 करोड़ ऐसे खातों के हजम किये।

जिस तरह से ये हरामखोर मंचों से चिल्ला रहा था। 18/09/2014 की एक आम चुनावी सभा में जिस तरह से आधार कार्ड के बारे में मनमोहन सिंग को कोस रहा था। आतंकवादी आधार कार्ड बनवा लेंगे और सुरक्षा को खतरा बनेंगे, अब जब देश में 16-17 से घुसने वाले रोहिंग्याओं तक 2 लाख से ज्यादा आधार कार्ड बनवाकर देश के नागरिक बन चुके है। जबकि काश्मीर, उप्र, राजस्थान, गुजरात में हजारों पाकिस्तानियों के जबकि करोड़ों बांग्लादेशियों ने, नेपालियों ने अपने आधार कार्ड बनवाकर सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

अब इस ढीठ को नहीं दिख रहा है। अब हर सेवा, बैंक खाता, विद्यालयों में प्रवेश, रेलवे टिकट में भी आधार कार्ड अनिवार्य कर जनता से वसूले करों से उन आतंकियों, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को पाला जा रहा है। जबकि भाषणों में कहा जाता था कि महंगाई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार सब दूर हो जायेगा। जबकि इस गिद्ध के सत्ता संभालने के बाद सब बढ़ गया।

कृषि उपज मंडी, देवास

मा. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म.प्र. सरकार का वंदन करती है। जिन्होंने कृषकों की उपज के उचित मूल्य के लिए भावांतर योजना की घोषणा कर 16/10/17 से 31/10/17 की अवधि में देवास जिले के कृषकों को भावांतर योजना में लगभग रु. 9,59,20,000 की राशि वितरित की।

निवेदन है कि कृषक बंधु अपनी उपज मंडी प्रागंण में ही विक्रय कर भावांतर योजना का लाभ उठाये।

अध्यक्ष
श्रीमती रामरतीबाई
बद्रीलाल जैसवाल

सचिव
जे.के. चौधरी

साप्ताहिक समय माया

भर्तियों और कर्मचारियों के अभाव में सरकार ध्वस्त होने के कगार पर

सेवानिवृत्ति 2 वर्ष बढ़ा, बचा जा सकता है भुगतान व कर्मचारी संकट में

शिक्षकों, चिकित्सकों की उम्र 65 में सेवानिवृत्ति की कर दी तो अधिकारियों, इंजिनियरों और कर्मचारियों की उम्र 62 तो की ही जा सकती हैं। इससे 50 प्रतिशत वेतन और गैच्युटी के भुगतान के ब्याज में ही वैतनिक कार्य लिया जा सकता है। भर्ती के बाद 6 माह से 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के बाद ही पूर्ण नियुक्ति और कार्य किया व लिया जा सकेगा। जबकि पुरानों के साथ तो अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी अधिकारी तत्काल तैयार है।

पूरे देश में विश्व व्यापार संगठन के बनाम विश्व के व्यावसायिक धूर्तों के संगठन ने विश्व के राष्ट्रों के प्राकृतिक और मानव निर्मित स्त्रोतों को अपने कब्जे में लेकर उससे पैसा लूटने और वहां की जनता को गुलाम बना कर रखने के लिए पहले विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विकास के नाम पैसा बांटकर कर्ज का घी पिलाया और फिर अपनी शर्ते थोंपी, सरकारें अपना खर्च कम करने के लिए 30 प्रतिशत कर्मचारियों अधिकारियों की कटौती करें ताकि उनके कुकर्मों पर अंगुली उठाने के लिए कम से कम लोग हो।

विश्व व्यापार धूर्त संगठन की शर्तों के चलते राष्ट्री की केन्द्र सरकार ने स्वयं और राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि वे अपना 30 प्रतिशत स्टाफ कम करने के लिए कि वे भर्तियां न करे।1990 के बाद स्वयं केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने बाबुओं, अधिकारियों, इंजिनियरों, डॉक्टरों से लेकर कृषि वैज्ञानिकों, शिक्षकों व अन्य सभी प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी। जबकि जनसंख्या, योजनाओं, न्यायालयों के निर्णयों, तकनीकों के बदलते अंदाज ने कानूनों के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता को दुगुना बढ़ा दिया, अब 27 वर्ष के लंबे अंतराल में स्टॉफ की सेवानिवृत्ति, मृत्यु और स्वास्थ्य के कारण स्वीकृत संख्याएं से भी कम स्टॉफ रह गया है। स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग के अनेकों महाविद्यालयों में अनेकों विषयों की पढ़ाई बंद करवा दी गई है। वैसे तो ये स्थिति हर विभाग की है, जहां आवश्यक कार्य भी ठेके पर या बाहर से करवाने पड़ रहे है। निसंदेह हर विभाग में नीचे से ऊपर तक कर्मचारियों, अधिकारियों की घोर कमी को तत्काल भती करने पर भी अगले 5 वर्ष तक पूरा नहीं किया जा सकेगा, सतत प्रशिक्षण के उपरांत भी, जिसका एक ही विकल्प बचता है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से लेकर प्रथम श्रेणी अधिकारियों तक जो पूर्णतः, स्वास्थ्य और कार्यशील होने के साथ ईमानदार व कर्मशील हो, जिनका पुराना इतिहास अच्छा हो, उनकी तत्काल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जानी चाहिए, इससे शासन-प्रशासन की अनेकों लाभ होगें एक तो आधी पेंशन के साथ 25-50 लाख रुपए भविष्य निधि के रूप में लौटाने से बचने, जो उनकी कुल तनख्वाह से ज्यादा होगा, अर्थात आधी पेंशन के साथ लाखों रुपए पर लगने वाला ब्याज की राशि से भुगतान किए जा रहे वेतन की राशि कम ही होगी, जबकि 17-18 में समस्त विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों जो कुल कार्यबल का 50 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण एक तरफ स्टॉफ की भारी कमी से प्रशासन ठप्प हो जायेगा तो दूसरी तरफ भविष्य व अन्य निधियों के भुगतान में शासन को हजारों करोड़ रुपए के साथ उस पर लगने वाला ब्याज भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए शासन को चाहिए कि वो तत्काल सेवानिवृत्ति की आयु को सभी वर्षों में 65 वर्ष कर दें, और सक्षम, कार्यशील, कर्मचारियों, अधिकारियों को जो 01.01.16 के बाद सेवानिवृत्ति से घर बैठ गए हैं। पुनः कार्य प्रारंभ करने की तिथि से वेतन निर्धारण कर पेंशन बंद कर वेतन देना शुरू कर दे। साथ ही सभी विभागों में मार्च 18 तक भर्तियां कर दे।

भारतीय संस्कृति और स्व. नाथूराम गोड़से

कांग्रेस की स्थापना तो 25/12/1885 को अंग्रेज ए ओ ह्यूम ने कोलकता में की ही इसलिए थी कि भारतीय जनता वैसे भी वर्तमान के आक्रोश को पनपने दिया जाए। भारतीय कांग्रेस अंग्रेजो की भारतीय अवैध पैदाइश है। मोहन गांधी, जवाहर नेहरू, लियाकत जिन्ना तीनों इंगुैड में पढ़े, अंग्रेजीयत में लिपटे, अंग्रेजो के ही भारतीय एजेंट थे। इन मक्कार, अय्याश, जालसाजों ने हजारों आजादी का आंदोलन करने वालों को अंग्रेजो के हाथ इसलिए मरवाया। ताकि इनकी लोकप्रियता और अंग्रेजो के प्रति वफादारी पर आंच न आये। देश को आजादी गांधी और नेहरू के कारण नहीं मिली। भारतीय आंदोलनकारियों और अंग्रेजी सेना मे शामिल भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्वयुध्द के बाद देश को आजादी देने से मुकरने पर जब बांबे नेवी के सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों को निपटा दिया। तब अंग्रेजो को भागने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आया। गांधी के अनशन करने के कारण पूर्व और पश्चिम दो पाक बनाये गये। तब इन तीनों धूर्तो को बुलाकर 99वर्ष की पट्टे की आजादी देकर सत्ता हस्तांतरित कर देश के तीन टुकड़े पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान जिसकी कमान जिन्ना और भारत की नेहरू को सौंपी। अंग्रेजो की भारत में 127 कंपनी 1947 तक काम कर रही थी। 15/8/1947 के बाद मात्र ईस्ट इंडिया को नेहरू गांधी ने देश छोड़ने को कहा। जबकि 126 कंपनी भारत में आज भी कार्य कर रही हैं। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का कनाट प्लेस दिल्ली में आज भी बोर्ड लगा है। विभाजन के समय 15 करोड़ हिन्दूओं के कत्लेआम हुआ जो पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से भारत की ओर खदेड़ने में हुआ। जिसके जिम्मेदार गांधी नेहरू ही थे। स्व गोडसे ने अगर यही कार्य 1वर्ष पूर्व 30/1/1946 में गांधी के साथ नेहरू का भी कर दिया होता तो आप आजादी पट्टे की न होकर पूर्ण आजादी होती, पाकिस्तान प्रांत होता न कि 3 राष्ट्र। जिस दिन मोहन गाँधी

और जवाहर नेहरू का पूरा सच सामने आयेगा। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ीयॉ इन की चौराहों पर लगी मूर्तिय्रों को साफ कर देंगी। वैसे सच को, 70 वर्षों तक अपनी सत्ता बचाने, कांग्रेस ने छुपा कर खूब झूठा इतिहास पढ़ाया। जिस दिन हुतात्मा गोडसे जी ने गांधी को मारने के 163 गंभीर कारणों को जनता ने व कांग्रेसीयो ने पढ़ लिया। उस दिन गांधी को मानने वाले कांग्रेसियों को भी गांधी के नाम से नफरत होने लगेगी। 90 प्रतिशत कांग्रेसी यदि असली राष्ट्रभक्त हैं। तो पहले वो सूची अवश्य पढ़ें जो हुतात्मा गोडसे जी ने न्यायालय में अपने प्रकरण की सुनवाई में न्यायाधीश के सामने रखे। जिसे सुनकर वहाँ खड़े लोग रोने लगे थे। फिर उन्हें उच्च व सवोच्च न्यायालय में अपील लगाने और सुनवाई का मौका दिये बिना ही साढ़े 21 महीनों में ही सारी कानूनी प्रक्रिया पूरा कर फांसी पर लटका दिया गया। क्योंकि कांग्रेस को डर था कि उसकी सचाई सामने आने पर कांग्रेस की धज्जियां बिखर जायेगी।

स्व. नाथूराम गोडसे दो समाचार पत्रों के संपादक और बुद्धिजीवी पत्रकार थे। इसलिए वो मोहन गांधी के 70 वर्षों के हिन्दू विरोधी, स्वतंत्रता को आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को मरवाने का, अंग्रेजों को सहयोग करने का इतिहास जानने के साथ आजादी मिलने या पट्टे की आजादी पर हस्ताक्षर करने व सत्तो हस्तांतरण के नाटक को भली प्रकार समझा था। साथ ही भारत के 3 टुकड़े करने के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं का कत्लेआम भी गांधी की खामोशी और पाकिस्तान को शह देने के कारण ही हुआ था। फिर गांधी का रुपए 55 करोड़ पाकिस्तान को देने का अनशन की नौटंकी, फिर पश्चिमी पाकिस्तान के लाहोर से ढांका 20 मील चौड़े जिसमें दोनों ओर 10-10 मील चौड़ी पट्टी मुस्लिम बस्तियों को बसाने कीच में लाहोर से ढांका तक भारत के सीने पर सड़क बनाने का वादा कर चुका था। जिस पर 12 फरवरी 1948 को हस्ताक्षर किया जाना था। जबकि सरदार पटेल और नेहरू इसके लिए बिल्कुल तैयार न थे। तब स्व. नाथुराम गोडसे ने देश को बचाने 30.01.1948 को अपनी मान प्रतिष्ठा त्याग गांधी की बिदाई पिस्तोल से निश्चित कर दी। यथार्थ में स्व. नाथूराम गोडसे स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े हिन्दू हितों को बचाने वाले क्रांतिवीर थे, जिन्हें 15.11.1949 को फांसी दे दी गई।

डीजल, पेट्रोल, में लूट का नया षड़यंत्र, अंबानी की मोटी कमाई

जनता को भ्रमित, लूटने हर दिन कीमत बदलने का खेल

पहले कीमतें गिराई, फिर चढ़ने लगी, चुनाव पूर्व रुपए 80 पेट्रोल, डीजल रुपए 70 कर दिया जाएगा, कांग्रेस सरकार में तो बहुत गालियां बकते थे कांग्रेसियों को

राष्ट्र के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में विराजे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बचपन बेहद गरीबी, आपराधिकता में गुजरा, जहां पैसा मंदिर और पूंजीपति देवता होता था, पैसा कमाने के लिए, जिसने अपनी मां के गहने चोरी करके बेच दिये हों, जिसके बाद घर के ही भाई बहनों ने जिसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई, जिसने मवालीगिरी करते हुए 14 से 35 वर्ष उम्र तक बिना पढ़ाई की, ब्लेकमेलिंग और छोटे-मोटे अपराध कर जिंदगी गुजारी हो, फिर उसी ब्लैकमेलिंग से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गया, उसे क्या खाक समझता है, अर्थशास्त्र, बैंकिंग कराधान, न्याया, सामाजिकता, देश संभालना, उसे समझता है तो जन-धन के पैसे से विदेशों में जाकर अपने आका पूंजीपतियों के लिए, राष्ट्रहित और जनहित को बलाए ताक पर रखकर उनके कार्य के लिए सौदेबाजी करना, मौज मस्ती करना, सैर-सपाटा और अय्याशी करना, कांग्रेस ने अंबानी बंधुओं को देश का आधा पेट्रोल सौंप रखा था, मोदी ने पूरा सौंप दिया उसके फायदे और लूट के लिए ताकि जनता हर दिन घटती-बढ़ती डीजल की मतों के गणित को समझ न सके। अंबानी महागिद्धों की फौज सरकारी कं. को रुपए 15 प्रति लीटर डीजल को रुपए 30 और

रुपए 20 के पेट्रोल के रुपए 40 में बेंचती है। इस पर 32 प्रश वेट और 4 प्रति लि. अलग से जोड़कर वसूल रही थी। दूसरी तरफ हर दिन घटाने बढ़ाने के खेल में सबको मोटी कमाई हो रही थी। हर पेट्रोल पंप की अपनी अलग कीमत थी। उसमें कं. में बैठे डिपो प्रबंधक से लेकर क्षेत्रीय स्तर के खाद्य व नागरिक आपूर्ति नियंत्रक व निरीक्षकों तक की कमाई का साधन बन चुकी थी। निसंदेह पंपो पर इसकी जांच और त्वरित कार्यवाही की इस लूट और मनमानी को रोकने की कोई व्यवस्था शासन स्तर के केन्द्र के पेट्रोलियम मंत्रालय ने उनके डिपो प्रबंधक से लेकर नीचे तक किसी ने भी नहीं की थी। इसके साथ ही पंपों की मिलावटी और कम नापने की लूट को 50 वर्ष बाद भी कोई रोक नहीं पा रहा है। उसके साथ ही अब हर दिन भाव बदलने की नई लूट का तांडव

गैस की कालाबाजारी और अनुदान में लूट का तांडव

पेट्रोलियम उत्पादों में लूट कि अलग क्रम में है। ईंधन गैस में सिलेंडर से गैस चोरी करना कीमतें बढ़ने पर बढ़ी हुई कीमत पुरानी बुकिंग पर वसूलना जबकि घटने पर बुकिंग की तारीख से वूसली करना, बुकिंग के बाद, रद्द करना दिखाकर, सिलेंडर बेंचकर हजम करना अनुदान के नाम पर 15 करोड़ उपभोक्ताओं में से मात्र 3 करोड़ को ही मुश्किल से अनुदान मिल पाता है। 2 करोड़ में अनुदान छोड़ दिया जबकि 10 करोड़ कनेक्शनों का रुपए 150 के औसत हिसाब से रुपए 1500 करोड़ प्रतिमाह डीलर कं, बैंक मिलकर हजम कर जाते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के खातों में से 5 करोड़ के खाते में अनुदान पहुंचा ही नहीं, 5 करोड़ के खाते में कभी कभार ही अनुदान पहुंचा अर्थात रुपए 12000 करोड़ प्रति वर्ष का भ्रष्टाचार इस अनुदान को बैंकों में जमा करने के नाम पेट्रोलियम मंत्रालय, कंपनियों के अधिकारियों के साथ मिलकर वितरक कर रहे है। दूसरी तरफ जिन खातों में 5 से ज्यादा लेन-देन होने अनुदान मिलने की तो दूर उल्टे ही बैंक 150 सौदा शुल्क और जीएसटी के नाम रुपए 25 से 50 करों के नाम करा जाता है। गैस एजेंसियों की जांच न तो कोई सरकारी एजेंसी करती है न कोई निजी जांच एजेंसी से खातों का अंकेक्षण करवाया जाता है। जो जनता के साथ खुली लूट का तांडव आधार कार्ड से जोड़ने अनुदान खातों में जमा करने के नाम पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इस पूरी मोदी सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय स्वयं ही चुप रहता है।

भारत में अकाल और बीमारियों से मौतों का कारण सोया रिफाइंड तेल

सोयाबीन, दलहन, तिलहन नहीं- सोया रिफाइंड नहीं पाम तेल सोया

केरल आयुर्वेदिक युनिवर्सिटी आंफ रिसर्च केन्द्र के अनुसार, हर वर्ष 20 लाख लोगों की मौतों का कारण बन गया है... रिफाईनड सोया तेल।

आखिर भाई राजीव दीक्षित जी के कहें हुए कथन सत्य हो ही गये!

रिफाईनड तेल से डीएनए डैमेज, आरएनए नष्ट, , हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन डैमेज, लकवा शुगर(डाईबिटीज), रक्तचाप नपुंसकता, कैंसर, हड्डियों का कमजोर हो जाना, जोड़ों में दर्द,कमर दर्द, किडनी डैमेज, लिवर खराब, कोलेस्ट्रोल, आंखों की रोशनी कम होना, प्रदर रोग, बांझपन, पाईलस, स्केन त्वचा रोग आदि!. एक हजार रोगों का प्रमुख कारण है। सोया पुर्नप्राप्त पाम तेल।

रिफाईनड तेल बनता कैसे हैं-

बीजों का छिलके सहित तेल निकाला जाता है, इस विधि में जो भी अशुकृता तेल में आती है, उन्हें साफ करने वह तेल को स्वाद गंध व कलर रहित करने के लिए रिफाइंड किया जाता है

धुलाई- वाशिंग करने के लिए पानी, नमक, कास्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब व अन्य खतरनाक तेजाब इस्तेमाल किए जाते है, ताकि अशुद्धता इससे बाहर हो जाएं। इस प्रक्रिया मै तारकोल की तरह गाडा वेस्टेज कीचड़ निकलता है जो कि टायर बनाने में काम आता है। यह तेल ऐसिड के कारण जहर बन जाता है।

उदासिनता- तेल के साथ कास्टिक या साबुन को मिक्स करके 180 सें.डिग्री पर गर्म किया जाता है। जिससे इस तेल के सभी पोस्टीक तत्व नष्ट हो जाते है।

गंध व रंगहीन- इस विधी में पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिसल) पी. ओ. पी. यह मकान बनाने मे काम ली जाती है/ का उपयोग करके तेल का कलर और मिलाये गये कैमिकल को 130 डिग्री पर गर्म करके साफ किया जाता है, जिससे रंग व गंध उड़ जाती है।

हायड्रोजेनिशन- एक टैंक में तेल के साथ निकोल और हाइड्रोजन को मिक्स करके हिलाया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं में तेल को 7-8 बार गर्म व ठंडा किया जाता है, जिससे तेल में पांलीमर्स बन जाते है, उससे पाचन प्रणाली को खतरा होता है और भोजन न पचने से सारी बिमारियां होती हैं।

निकेल- एक प्रकार का उत्प्रेरक धातु होता है जो हमारे शरीर श्वसन तंत्र को (यकृत, त्वचा, स्वस्थ रखने, डीएनए व आरएनए) को भयंकर नुकसान पहुंचाता है। जिससे शरीर को संबंधित बीमारियां घेर लेती है।

रिफाईनड तेल के सभी तत्व नष्ट हो जाते है और तेजाबी रसायन (कैमिकल) मिल जाने से यह भीतरी अंगों को नुकसान पहुंचाता है।

जयपुर के प्रोफेसर श्री राजेश जी गोयल ने बताया कि, गंदी नाली का पानी पी लें, उससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे शरीर में प्रति रोधक क्षमता उन बैक्टीरिया को लडकर नष्ट कर देता है, लेकिन रिफाईनड तेल खाने वाला व्यक्ति की अकाल मृत्यु होना निश्चित है!

दिलथाम के पढ़े-

हमारा शरीर करोड़ों सेल्स (कोशिकाओं) से मिलकर बना है, शरीर को जीवित रखने के लिए पुराने सेल्स नई कोशिकाओं में बदलते रहते है नये सेल्स (कोशिकाओं) बनाने के लिए शरीर खुन का उपयोग करता है, यदि हम रिफाईनड तेल का उपयोग करते है तो खुन मे विषाक्तता की मात्रा बढ़ जाती है व शरीर को नए सेल बनाने में अवरोध आता है, तो कई प्रकार की बीमारियां जैसे- कैंसर,मधुमेह,हार्ट अटैक, किडनी खराब, एलर्जी, पेट में घाव, नपुसंकता, अस्थि रोग, अवसाद आदि हजारों बिमारियां होगी।

रिफाईनड तेल बनाने की प्रक्रिया से तेल बहुत ही मंहगा हो जाता है, तो इसमे पांम आंयल मिक्स किया जाता है! (पांम आंयल स्वयं एक धीमी मौत है)

सरकार का आदेश- हमारे देश की नीतियां अमरिकी सरकार के इशारे पर चलती है। अमरीका

का पांम खपाने के लिए,मनमोहन सरकार ने मोटा कमीशन हजम कर एक अध्यादेश लागू किया कि, प्रत्येक तेल कंपनियों को 40 प्रतिशत खाद्य तेलों में पांम आंयल मिलाना अनिवार्य है, अन्यथा लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा!

इससे अमेरिका को बहुत फायदा हुआ, पांम के कारण लोग अधिक बीमार पडने लगे, हार्ट अटैक की संभावना 99 प्रश गई, तो दवाइऱ्यां भी अमेरिका की आने लगी, ह्दय मे लगने वाली स्प्रिंग (पेन की स्प्रिंग से भी छोटा सा छल्ला), दो लाख रुपये की बिकती है,

यानी कि अमेरिका के दोनो हाथों में लड्डू, पांम भी उनका और दवाइऱ्यां भी उनकी!

अब तो कई नामी कंपनियों ने पांम से भी सस्ता,, गाड़ी में से निकाला काला आंयलड (जिसे आप गाडी सर्विस करने वाले के छोड आते है)

वह भी रिफाईनड कर के खाद्य तेल में मिलाया जाता है, अनेक बार अखबारों में पकड़े जाने की खबरे आती है।

सोयाबीन एक दलहन है, तिलहन नही...

दलहन में... मुंग, मोठ, चना, सोयाबीन, व सभी प्रकार की दालें आदि होती है, जो द्विदलीय होती है।

तिलहन में... तिल, सरसों, मुमफली, नारियल, बादाम, करड़ी, अलसी आदि आती है।

अतः सोयाबीन तेल , शुद्ध पांम आंयल ही होता है। पांम आंयल को रिफाईनड बनाने के लिए सोयाबीन का उपयोग किया जाता है।

सोयाबीन की एक खासियत होती है कि यह,

प्रत्येक तरल पदार्थों को सोख लेता है,

पांम आंयल एक दम काला और गाढ़ा होता है,

उसमे साबुत सोयाबीन डाल दिया जाता है जिससे सोयाबीन बीज उस पांम आंयल की चिकनाई को सोख लेता है और फिर सोयाबीन की पिसाई होती है, जिससे चिकना पदार्थ तेल तथा आटा अलग अलग हो जाता है, आटा से सोया मंगोडी बनाई जाती है!

आप चाहें तो किसी भी तेल निकालने वाले के सोयाबीन ले जा कर, उससे तेल निकालने के लिए कहे! महनताना वह एक लाख रुपये भी देने पर तेल नही निकालेगा, क्योंकि. सोयाबीन का आटा बनता है, तेल नही!

फॉर्च्यून.. अर्थात.. आप के और आप के परिवार के फ्यूचर का अंत करने वाला.

सफोला... अर्थात.. सांप के बच्चे को सफोला कहते है!

5 वर्ष खाने के बाद शरीर जहरीला

10 वर्ष के बाद.. सफोला (सांप का बच्चा अब सांप बन गया है.

15 साल बाद.. मृत्यु... यानी कि सफोला अब अजगर बन गया है और वह अब आप को निगल जायेगा.!

आखिर भारत में इतना विष तेल में, खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों आदि का खाने के बाद महामारी क्यों नहीं फैलती, इसका सबसे प्रमुख कारण है, कि सब्जीयों को तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले मसाले यथा हल्दी, मिर्ची, धनियां, हींग, जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी अपने आपमें मानव शरीर के श्रेष्ठ औषधियां है। जो इन विषों के दुष्प्रभाव को नष्ट करती रहती है। वह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है।

पहले के व्यक्ति 90.. 100 वर्ष की उम्र में मरते थे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती थी, क्योंकि.उनकी सभी इच्छाए पूर्ण हो जाती थी।

और आज... अचानक हार्ट अटैक आया और कुछ ही देर में मर गया....?

उसने तो कल के लिए बहुत से सपने देखें है, और अचानक मृत्यु..?

अधुरी इच्छाओं से मरने के कारण.. प्रेत योनी मे भटकता है।

राम नही किसी को मारता.... न ही यह राम का काम!

अपने आप ही मर जाते है.... कर कर खोटे काम!!

गलत खान पान के कारण, अकाल मृत्यु हो जाती है!

सकल पदार्थ है जग माही..!

कर्म हीन नर पावत नाही..!!

अच्छी वस्तुओं का भोग,.. कर्म हीन, व आलसी व्यक्ति संसार की श्रेष्ठ वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकता!

तन मन धन और आत्मा की तृप्ति के लिए सिर्फ कच्ची घाणी का तेल, तिल सरसों, मुमफली, नारियल, बादाम आदि का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए! पोस्टीक वर्धक और शरीर को निरोग रखने वाला सिर्फ कच्ची घाणी का निकाला हुआ तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए!

आज कल सभी कम्पनी.. अपने प्रोडक्ट पर कच्ची घाणी का तेल ही लिखती है!

वह बिल्कुल झूठ है.. सरासर धोखा है!

कच्ची घाणी का मतलब है कि,, लकड़ी की बनी हुई, औखली और लकडी का ही मुसल होना चाहिए! लोहे का घर्षण नहीं होना चाहिए. इसे कहते है.. कच्ची घाणी.

जिसको बैल के द्वारा चलाया जाता हो!

आजकल बैल की जगह मोटर लगा दी गई है!

लेकिन मोटर भी बैल की गती जितनी ही चले!

लोहे की बड़ी बड़ी सपेलर (मशिने) उनका बेलन लाखों की गती से चलता है जिससे तेल के सभी पोस्टीक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वे लिखते है.. कच्ची घाणी... जो कि सरासर जनता के साथ धोखा और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है। जैसे-जैसे यह सच जनता को समझ आयेगा, कम से कम धनाढ्य वर्ग सोया तेल खाना बंद कर देगा। बाजार में छोटी तेल निकालने वाली मशीनें आ चुकी हैं। जिनसें 50-60 तामपान पर तेल निकालकर मूंगफली, तिल्ली,सरसों का शुद्ध तेल प्राप्त कर उपयोग किया जा सकता है। धीरे-धीरे भारत में मुख्य रूप से मालवा में सोयाबीन की खेती कम कर देनी चाहिए। आने वाले समय भारत के तिलहनों सरसों, तिल, मूंगफली की मांग बढ़ेगी और सोया की मांग घरेलू मशीनों से तेल निकालने के कारण समाप्त हो जायेगा जो कि पाम तेल है। हमारे देश की जलवायु के लिए हमारे पारपंरिक तिलहन बीज जिसमें सूरजमुखी, करड़ी, अलसी, महुआ, मूंगफली, सरसों, तिल ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। ये विदेशी अमेरिकाा कं. की चाल ही है कि सोया तेल के नाम, जबकि वह पूर्णतः दलहन है। अपने यहां का पाम तेल बेंचना। उदाहरण हमारे नीति निर्धारकों ने 40 प्रतिशत सभी खाद्य तेलों में मिलाने के लिए मजबूर कर पूरे देश को बीमारियां बांट खूब अपनी दवाइयां और मशीनें बेंच रहे हैं।

मध्य प्रदेश के 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन में एक बार फिर उजागर हुआ प्रमाणित घोटाला

भोपाल। मध्यप्रदेश के 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन घोटाला प्रमाणित हो गया है। मेडीकल यूनिवर्सिटी ने अपनी जांच में कुल 179 सीटों पर फर्जीवाड़ा कर एडमिशन दिए जाने की पुष्टि की है। बता दें कि मध्यप्रदेश में इस तरह के गोरखधंधे में 1 सीट के लिए 1 करोड़ रुपए तक लिए जाने का खुलासा व्यापमं घोटाले के समय हुआ था। इस प्रकार यह कुल 179 करोड़ का घोटाला है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन कॉलेजों ने 179 ऐसे छात्रों को एडमिशन दे दिया जो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं थे। मामले की जांच कर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आरएस शर्मा ने सभी 179 दाखिलों के रिजल्ट रोकने और डीएमई को इनके दाखिले निरस्त करने की अनुशंसा की है। मामला एनआरआई कोटे में एडमिशन का है। इस कोटे में उन उम्मीदवारों को एडमिशन मिलता है जो अप्रवासी भारतीय हों। जांच में पाया गया कि एक भी स्टूडेंट एनआरआई नहीं था। बता दें कि ये सभी वो मेडिकल कॉलेज हैं जिनके पास या तो डायरेक्टर पॉलिटिकल कनेक्शन है या फिर किसी पॉलिटिकल पॉवर का संरक्षण हासिल है।

जिन के बारे में पूरा देश जनता है ख़ास बात ये है कि इनमे से अधिकांश पहले से ही घोटाले के दागी है । मगर सरकार के लोग अपने हितलाभ जुड़े होने के कारण अपराध की व्याख्या भी अपने हिसाब से करते है अपराध में परोक्ष रूप से संदिग्ध है ।

मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के कॉलेज जिनका हुआ एडमिशन में जानबूझकर फर्जीवाड़ा

भोपाल के एडवांस इंस्टीटयूट ऑफ मेडीकल साइंस में 22एनआरआई सीट,

देवास के अमलताल मेडीकल कॉलेज में 21 एनआरआई सीट,

चिरायु मेडीकल कॉलेज भोपाल की 23 एनआरआई सीट,

मॉर्डन इंस्टीटयूट ऑफ मेडीकल साइंस कॉलेज की 23 एनआरआई सीट,

आरडी गॉर्डी मेडीकल कॉलेज उज्जैन की 19 एनआरआई सीट,

साक्षी मेडीकल कॉलेज गुना की 25 एनआरआई सीट,

श्री अरविंदो मेडीकल कॉलेज इंदौर की 23 एनआरआई सीट

और सुखसागर मेडीकल कॉलेज जबलपुर की 23 एनआरआई सीट्स शामिल हैं.

केन्द्र, राज्य व सर्वोच्च न्यायालय के सारे नियम कानून हिन्दुओं पर ही क्यों थोपे जा रहे है

सत्ताधीशों ने बाल विवाह, दो बच्चे, एक पत्नी सब हिन्दुओं पर ही थोपे

मंदिरों के चढ़ावे सरकारों के चाते में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, मुस्लिमो और ईसाईयों मिशनरियों के देशी विदेशी चंदे पर कोई रोक-टोक, जांच पड़ताल नहीं

भारत की पट्टे की आजादी के भले ही 70 वर्ष हो गये है। पर शासन अभी भी ब्रिटेन के ही इशारों पर चलाया जा रहा है। अंग्रेजों ने 200 साल देश पर राज कर यह तो जान ही लिया था कि मुस्लिमों की कट्टरता पर हाथ डालने से बेहतर होगा कि हिन्दुओं को दबाया जाए और शोषण किया जाए, फिर लाखों की मौत, सैकड़ों को फांसी पर लटकाये जाने के बाद जब बांबे नेवी के सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के वादे के मुताबिक आजादी देने से मना कर दिया तो बांबे नेवी के सैनिकों को जब अंग्रेज अधिकारियों का भारी वध किया तब अंग्रेजों ने डरकर देश छोड़कर जाने का मन बनाया और अपने अंग्रेजी एजेन्टों मोहन गांधी, जवाहर लाल नेहरू, मो. जिन्ना जो तन से भारतीय और मन से काले ब्रितानी थे। उनको बैठाकर पट्टे की आजादी पर हस्ताक्षर करवाकर सत्ता हस्तांतरण किया स्वाभाविक था उन की बनाई पार्टी के ही सत्ता सौंपी गई।

जिसने आजादी के बाद हिन्दुओं पर ही दो बच्चों, बाल विवाह, एक पत्नी के कानून थोंप हिन्दुओं को 12 राज्यों में अल्पसंख्यक बना दिया।

बड़ी ही लंबी लड़ाई के बाद हिन्दुओं को समझे जाने वाली पार्टी की सरकार भी आई, तो भी उसने हिन्दुओं की रक्षा उनकी जनसंख्या बढ़ोत्री की अपेक्षा मुस्लिमों और ईसाइयों के पक्ष में ही सारे कार्य कर रही है। साथ ही देश की न्यायिक व्यवस्थाओं में भी जिला व सत्र न्यायालयों से लेकर उच्च व सर्वोच्च न्यायालय तक सब न केवल सामाजिक व्यवस्थाओं में दखअंदाजी करने से लेकर पूजन हवन व त्यौहारों की प्रथाओं आदि तक में हस्तक्षेप करने के साथ ही दिशा निर्देश तक देते रहते हैं। जैसे यहां पर बैठे न्यायाधीश बहुत बड़े पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, समाजशास्त्री हो, जबकि उनका कार्य न्याय करना है कि केवल हिन्दुओं के पूजन कार्यों में, समाज की प्रथाओं में हस्तक्षेप करना। दूसरी ओर मुस्लिमों की सामाजिक प्रथाओं में जबकि उन प्रथाओं से वह स्वयं समाज ही ज्यादा परेशान होता है। हस्तक्षेप करने और निर्देश देने समान आचार संहिता मानने के लिए दबाव बनाने से साफ इंकार कर देता है। इसी तरह हिन्दुओं के मंदिरों में आये धन और चढ़ावे पर न केवल सरकार नियंत्रण करती है उसके धन को सरकारी खजाने में जमा कर लिया जाता है। जबकि ईसाई मिशनरियां और मुस्लिमों को देशी-विदेशी संस्थाओं प्राप्त धन जो हर चर्च और सभी मस्जिदों को प्राप्त होता है। उसका हिसाब किताब पूंछने और जानने की औकात न तो सरकारो में थी और न ही न्यायालयों में कि वे पूछ सकें कि कहां से कितना धन कब और कैसे प्राप्त हुआ और कैसे खर्च किया। जबकि मुस्लिमों में धर्म में ही जकात देने की स्थाई परंपरा है। जो उनके समाज के हितों में उपयोग की जाती है। जबकि हिन्दुओं में मर्जी से दान देने की ही शास्त्र समत व्यवस्थाएं है।

हिन्दू मंदिरों में प्राप्त धन का उपयोग हिन्दुओं के समाज कल्याण के साथ, वेदों की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, शालाओं के विकास, आयुर्वेदिक औषधालयों, महाविद्यालयों के विकास में ही सरकार को खर्च करनी चाहिए परंतु मंदिरों में प्राप्त चढ़ावे जिसमें सोने, चांदी के आभूषणों और नगद धन को सरकार अपने कब्जे में ले लेने के साथ मंदिरों में दर्शनार्थ प्रवेश शुल्क, प्रसाद शुल्क, पूजा शुल्क आदि की वसूली करने से निर्धन वर्ग भगवानों के मंदिरों में भी अपनी निर्धनता के कारण ठगाया हुआ अनुभव करता है। परंतु इस पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप और निर्देश नहीं देता। जबकि इसी कारण भारत से संस्कृत, वेदों का, उपनिषदों और पुराणों का अध्ययन हमारे ही देश से लुप्त हो विदेशी पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में स्थाई पाठ्यक्रम में शामिल होकर उन्हें हमसे श्रेष्ठ बना रहा है। विदेशी वेदों, पुराणों की वैज्ञानिकता से शास्त्रों को तोलने में लगे है। हमारे देश में हमारी वेदों की ऋचाओं, उपनिषदों, पुरणों, गीता आदि का अध्ययन स्कूलों में पढ़ाना सांप्रदायिक है। जबकि मुस्लिम और ईसाई राष्ट्रों में वहीं सब स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना प्राचीन परंपराओं से वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति का आधार ये सारी व्यवस्थाएं अभी भी भारत में ब्रिटेन के इशारे पर ही चल रही है। जैसा कि उन्होंने 200 वर्ष के शासन में रहते हुए किया। हमारे राष्ट्र में अपनी संस्कृति की महानता पढ़ाते रहे ।

भूगोल, अर्थशास्त्र, रसायन, अर्थगणित, ज्योतिष,गृहों की चाल व गणना, भौतिकीय, सौर मंडल, चिकित्सा, आयुर्वेद आदि पर इन्हीं शास्त्रों के अध्ययन से हमे ही सिखाते है। पर हमारे भारत की सरकारों ने अपने ही देश में इन वेदों, पुराणों, आदि के अध्ययन की व्यवस्था हिन्दुओं के हड़पे धन से भी 70 वर्ष की आजादी के बाद भी कभी नहीं की। उल्टे ही अपने वोट बैंक को मजबूत करने अनु. जाति, जनजाति को आरक्षण में उलझाकर उनके नाम का विकास का धन हड़पते रहे और समाज की समुचित उन्नति की अपेक्षा आपस में ही हिन्दुओं को अंग्रेजों की तरह लड़वाते रहे।

भाव-अंतर व्यापारी और सरकार मिल हजम करेंगे आधार-अंतर

जनधन को भावांतर में लुटा लूटेंगे व्यापारी व सरकारी तंत्र

जब प्रदेश की हर छोटी-बड़ी मंडी के द्वार पर देश की मंडियों के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर हर उत्पादन की दर चलती रहती है। तो व्यापारी क्यों 10 से 30 प्रतिशत तक कम दर माल खरीद किसान को भुगतान करता है, फिर समर्थन मूल्य से कम पर बेंची गई। फसल के खरीद किसान को भुगतान करता है,फिर समर्थन मूल्य से कम पर बेंची गई फसल के भावों कें अंतर को सरकार कृषकों के खातें में जमा करने का कार्य करती है मप्र सरकार। मप्र के मुख्यमंत्री शिव चौहान, राष्ट्रीय स्वयं संघ से प्राप्त सूचनाओं और निर्देशों का अक्षरश पालन करते हैं। संघ ने निर्देशित किया कि किसान आदिवासी और दलित वर्ग सरकार से बहुत नाराज है। तत्काल शिव सरकार ने सभी कृषकों को रिझाने और व्यापारियों के माध्यम से आधा धन वापिस बुलाकर हजम करने कृषि उत्पादों की मुख्य फसलों का शासकीय मूल्य निर्धारित कर दिया यदि उससे कम में व्यापारी माल खरीदेगा मंडी ये तो उसके भावों के अंतर की राशि मप्र सरकार जनधन से लूटकर सीधा किसानों के खातों में जमा करेंगे, स्वाभाविक था तत्काल ही व्यापारियों ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3050 मॉडल मूल्य प्र.क्वी. रुपए 2580 उड़द मॉडल मूल्य प्रति क्वि. 3000, समर्थन मूल्य रुपए 5400, भावांतर की राशि रुपए 2400/-, मूंगफली मॉडल मूल्य रुपए 3720/-, समर्थन मूल्य रुपए 4450/-, भावांतर की राशि रुपए 730/-, मूंग मॉडल मूल्य रुपए 4120/-, समर्थन मूल्य रुपए 3575/-, भावांतर की घोषणा के बाद 55-60 रुपए की मूंगफली की खरीद को आसानी समर्थन मूल्य पर खरीद में रुपए 30 प्रति किलो खरीद आसानी से से राष्ट्रीय स्तर पर रुपए 8000 से 12000 क्विंटल में बेचेगा। अर्थात वह तो रुपए 30 का माल 90 से 120 में बेचेंगा बदले में किसान को रुपए 3000/- का भुगतान करेगा। सरकार का भावांतर योजना का लाभ जब मिलेगा तब जबकि शासन के दलाल कृषि व मंडी अधिकारियों की मुट्ठी में 10/-15 प्रतिशत का चढ़ावा चढ़ायेगा दूसरी तरफ व्यापारियों के पास सैकड़ों किसानों के जिनसे उसने पूर्व में खरीदी की थी उनके खातों में फर्जी खरीद दिखाकर भावांतर का पैसा हस्तांतरण करेगा, फिर वही माल दूसरों से खरीदना दिखाकर फर्जी खरीदी-बिक्री के माध्यम और मंडी अधिकारियों और निरीक्षक के साथ मिलकर अरबों की हेराफेरी की जायेगी, जबकि वास्तविक उत्पादक किसान अपनी लागत के लिए भी भटकेगा जैसा कि प्याज की खरीद बिक्री में फर्जी खरीद बिक्री के माध्यम से जिला खाद्य अधिकारियों और निरीक्षकों को धन बांटकर व्यापारियों और अधिकारियों से कर लेगी। बदले में 28 प्रतिशत कर के साथ रुपए 4 अतिरिक्त पेट्रोल पर रुपए 3, डीजल और गैस में वसूलेगी। जनधन का भांति-भांति, नाना प्रकार से लूट, अंतकाल पछतायेगा जग सत्ता जायेगी छूट।

स्मार्ट सिटी के नाम निगमों की डकैती का तांडव

एक तरफ निर्माण के नाम अरबों रुपए की कमीशन वसूली दूसरी तरफ लाखों की बेरोजगार बनाना

मोदी के केन्द्रीय सत्ता में आने के बाद पूंजीपतियों के इशारे पर नाच और मोटा कमीशन वसूलने के लिए लाखों करोड़ सफाई और लेन-देन में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकारों के वसूलने के साथ नगर निगमों में भी चारों तरफ भारी भ्रष्टाचार और लूट का तांडव चल रहा है। जहां सारे टर्न को प्रोजेक्ट में मोटे कमीशन के लिए 4 गुने से 10 गुनी दरों पर सारे निर्माण कार्य सफाई कार्य, विद्युतीकरण कार्य स्तरहीन तो करवाये ही जा रहे है। वहीं दूसरी तरफ अकेले इंदौर में 8000 से ज्यादा गायों को सड़क से बिना हिसाब किताब रखकर गौशालाओं में रखना बताया गया। उन्हीं गायों को रात्रि में गौशालाओं के कर्मचारियों ने प्रति गायों को रुपए 10-12 हजार में कसाइयों को बेच रहे हैं। गौरक्षा का पाखंड करने वाली भाजपा इस सारे घटनाक्रम पर चुप है। इसी क्रम में सड़क की सीमेंटीकरण के समय उचित जलनिकासी का व्यवस्था नहीं की गई, बाद में अधिकांश सड़के फोड़कर अब पाइपलाइन डालने,फिर इसी सीमेंटीकरण के नाम पर पार्षदों ठेकेदारों ने मिलकर करोड़ों हजम किए। फिर सड़कों पर बैठकर, हाथ ठेलों पर छोटा-मोटा व्यवसाय करने वालों के ठेले जप्त कर माल और ठेले जब्त कर पूरे प्रदेश के महानगरों, 51 जिलों के मुख्यालयों में लाखों को बेरोजगार कर दिया जबकि उनसे निगम कर्मचारी और क्षेत्रीय पुलिस रुपए 100 -500 तक प्रतिदिन वसूलती थी। ये नीच गिद्धों की फौज ने केवल लाखों को बेरोजगार करती है वरन उनके ठेलों का बाले-बाले दूसरों को बेचने, ठेलों को तोड़कर कबाड़ बेंचने से मोटी कमाई कर रही है। लाखों को बेरोजगार कर उनसे जुड़े परिवार के 5-10 लोगों को भूखा मरने अवश्य छोड़ देती है। स्वाभाविक है ठेलों पर सब्जी व फल-फ्रूट नहीं बिकेंगे तो आम नागरिकों को रिलायंस, बिग बाजार आदि के शॉपिंग मॉल्स की तरफ जाना मजबूरी बनेगी। जिसका ये महीना शॉपिंग माल से भी वसूलते हैं। मान भी लिया जाए कि ठेले यातायात बाधित कर रहे वो भी गिद्धों ठेले तोड़ने, माल बिखेरने, फेंकने और जब्त कर हजम करने वाले कौन? बेशक डराधमकाकर उन्हें छोटी गलियों में खड़ा होने के लिए कहा जा सकता है। पर पूंजीपतियों के इशारों पर नाचने वाले गिद्धों उन मेहनतकश मजदूरों और उनके परिवार को तुम्हारे बाप रोटी देंगे। फिर वे रोजगार होने पर चाकू छुर्रे चलायेंगे, लूटमार करेंगे तब सबसे पहले तुम्ही को लक्ष्य बनायेंगे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि - एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय - मोबा. 9425125569